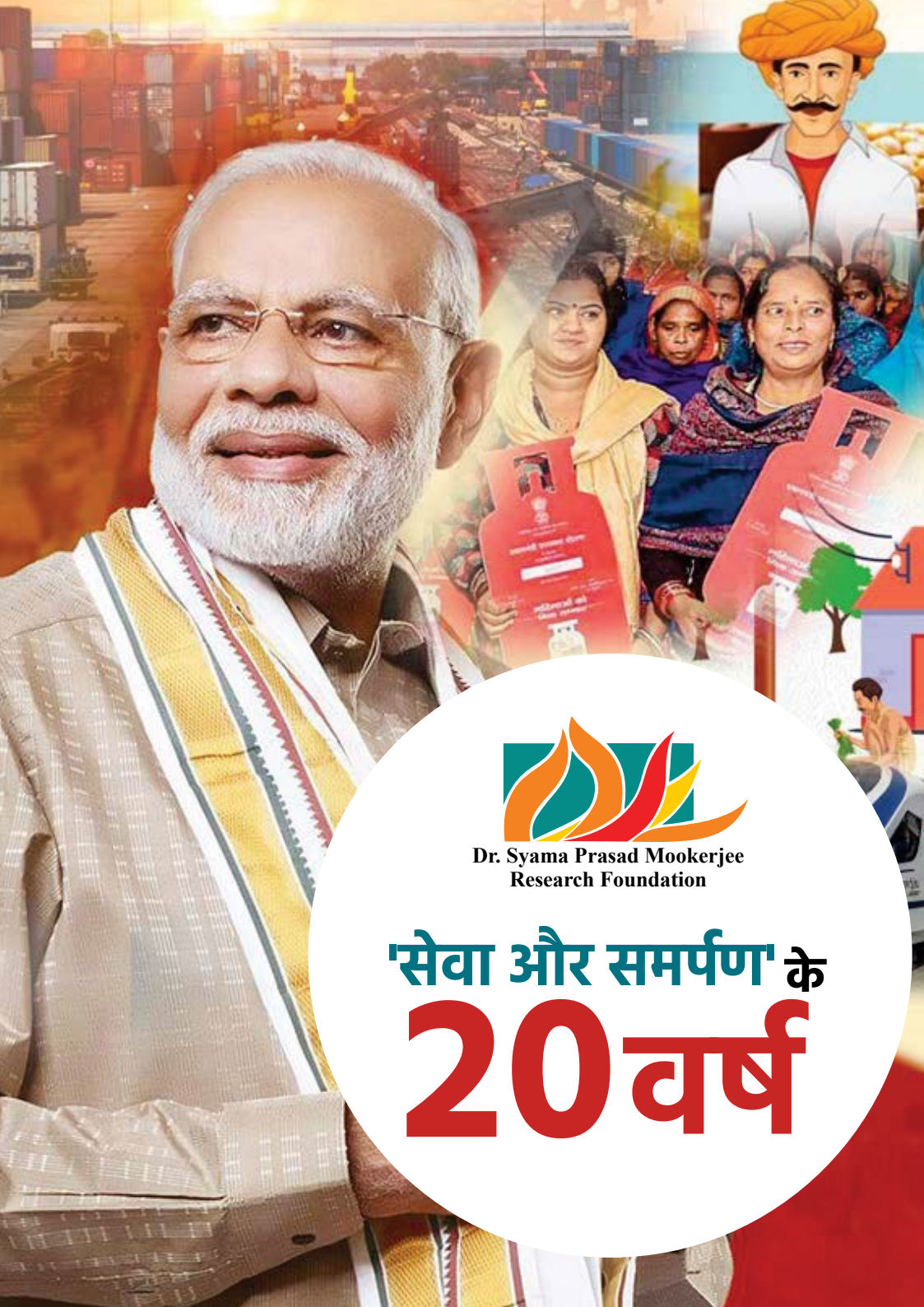

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

'सेवा और समर्पण' के 20 वर्ष

संपादन

अभय सिंह

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

रिसर्च टीम

मनुजम पांडेय

रिसर्च एसोसिएट
डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

डिजाइन

अजित कुमार सिंह

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-69047014

विषय सूची

भूमिका

1.	प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: अनुभव एवं संघर्षों की आँच में तपकर निखरा-चमका लोकप्रिय राजनेता - **प्रणय कुमार**	5
2.	प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: उनकी बातों में है माटी की महक - **संजय द्विवेदी**	10
3.	बेमिसाल बीस वर्ष - **डॉ दिलीप अग्निहोत्री**	13
4.	भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार मोदी - **अरविंद जयतिलक**	17
5.	महिला सशक्तिकरण को नए आयाम देती मोदी सरकार - **डॉ. खुशबू गुप्ता**	22
6.	सरकारी योजनाओं से भारत को सशक्त बनाने की पहल - **सतीश सिंह**	25
7.	श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में गरीबी समाप्त करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश को भारत की ओर मोड़ने में सफलता पाई है - **प्रहलाद सबनानी**	29
8.	नरेन्द्र मोदी: असाधारण, कुशल एवं प्रभावी वक्ता - **लोकेन्द्र सिंह**	33
9.	धारा-370 हटने से देश की अखंडता हुई अक्षुण्ण - **प्रमोद भार्गव**	37
10.	किसानों की बदहाली तभी दूर होगी, जब वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे - **रमेश कुमार दुबे**	41
11.	'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' को साकार करती मोदी सरकार - **अजय धवले**	44
12.	भारतीय शिक्षा को नया आयाम दे रहे हैं पीएम मोदी - **प्रो. निरंजन कुमार**	47

भूमिका

भारत जैसे विशाल, बहुभाषी और बहुआयामी देश को विकास के एक नए युग में ले जाने का संकल्प लेकर पूरी निष्ठा से कर्म पथ पर अग्रसर रहने वाले प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष पूरे हो गए हैं. जिसकी शुरुआत गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में हुई थी और विकासपुरुष के रूप में प्रधानमंत्री बनने के बाद भी यह यात्रा अनवरत जारी है. जनकल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन से जनता का विश्वास प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पर निरंतर बना हुआ है. जनता से मिले इस अपार स्नेह और विश्वास के कारण ही वह जनता के बीच सर्वमान्य हैं. गरीबों, पीड़ितों और वंचितों के लिए किए गए उनके कार्य सफलता के अनुपम सोपान की भांति हैं. प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मजबूत इच्छाशक्ति तथा आपदा को अवसर में बदलने की कार्यशैली ने उन्हें गुजरात के भुज में आए भूकंप से लेकर कोरोना महामारी से जंग तथा राममंदिर निर्माण और अनुच्छेद 370 हटाने जैसे बड़े फैसले लेने में सक्षम बनाया है. 2014 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने कहा था 'मेरी सरकार गरीबों की सरकार होगी'. आज सात सालों बाद जनधन योजना के तहत 43 करोड़ से अधिक बैंक खाते खुले हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना से 2 करोड़ से अधिक आवास बने हैं, उज्ज्वला योजना के तहत 8 करोड़ से अधिक माताओं-बहनों का जीवन धुंए से मुक्त हुआ है, सौभाग्य योजना के तहत 2 करोड़ से अधिक घरों को बिजली पहुंचाई गई है, स्वच्छ भारत मिशन के तहत 11 करोड़ से अधिक शौचालय निर्माण हुआ है, आयुष्मान भारत, डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मुद्रा योजना आदि समेत देश के किसानों की आय को दोगुनी करने हेतु अनेकों योजनाएं क्रियान्वित हो रही हैं. यह दर्शाता है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार 'सबका-साथ, सबका-विकास, सबका-विश्वास, सबका प्रयास' के मंत्र को आत्मसात कर बिना किसी भेदभाव के शोषित, वंचित समेत सभी वर्ग का समुचित विकास कर रही है. बहरहाल प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उस समय से ही वह जनता के हितों को लेकर चिंतित रहते थे और आज प्रधानमंत्री के रूप में भी उनके जीवन का ध्येय 'सेवा और समर्पण' ही है.

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन ने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन में 20 वर्ष पूरे होने पर विभिन्न लेखकों द्वारा लिखित व समाचार पत्रों में प्रकाशित आलेखों में से कुछ चयनित आलेखों को संकलित करके एक बुकलेट का स्वरूप दिया है. इस बुकलेट के माध्यम से पाठक एक ही जगह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के व्यक्तित्व व कार्यशैली के विभिन्न पहलुओं को समझ सकता है. इस संकलन में जितने भी लेख लिए गए हैं, सभी लेखों के लिए अधिष्ठान लेखकों एवं समाचार पत्रों के प्रति आभारी है.

डॉ. अनिर्बान गांगुली

निदेशक, डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: अनुभव एवं संघर्षों की आँच में तपकर निखरा-चमका लोकप्रिय राजनेता

प्रणय कुमार

राजनीति भी व्यापक मानवीय संस्कृति का एक प्रमुख आयाम है। भारतीय जनमानस के लिए राजनीति कभी अस्पृश्य या अरुचिकर नहीं रही। स्वतंत्रता-आंदोलन के दौर से ही राजनीति जनसेवा एवं सरोकारों के निर्वाह का सशक्त माध्यम रही। स्वतंत्रता के बाद के प्रारंभिक दशकों में भी राजनीति जनसरोकारों को लेकर चली। बाद के दिनों में एक ऐसा कालखंड अवश्य आया जब जातिवाद, क्षेत्रवाद, वंशवाद एवं क्षद्म धर्मनिरपेक्षता की घोल पिलाकर मतदाताओं को लामबंद कर सत्ता बनाए रखने के कुचक्र रचे गए और उसमें कुछ दशकों तक राजनीतिज्ञ सफ़ल होते भी दिखे। परंतु जैसे काठ की हांडी बार-बार नहीं चढ़ाई जा सकती वैसे ही सफ़लता की गारंटी माने जाने वाले ये सूत्र भी विफ़ल हुए। भारतीय जनमानस का इससे मोहभंग हुआ। जातिवाद एवं सूडो सेकुलरिज़्म का झुनझुना लोगों को दो वक्त की रोटी नहीं दे सकता, इसलिए लोग इससे विमुख होकर विकास और सेवा की राजनीति की आकांक्षा और स्वप्न संजोने लगे। आम मतदाताओं के इस मन और मिज़ाज को गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री ने इक्कीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में ही पढ़ और समझ लिया था। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए ही विकास को राजनीति के केंद्र में स्थापित करना शुरू कर दिया था। गुजरात में विकास की रफ़्तार को देखकर बाक़ी राज्यों को भी लगने लगा कि यदि दिशा, दृष्टि और इच्छाशक्ति हो तो जनभावनाओं एवं जनाकांक्षाओं को साकार किया जा सकता है। मुख्यमंत्री रहते हुए भी नरेंद्र मोदी की एक राष्ट्रीय अपील थी। राज्येतर जनाधार था। वे राजनीति में एक उम्मीद बनकर उभरे। यदि हम तटस्थ एवं ईमानदार विश्लेषण करें तो यह दावा अतिरेकी नहीं होगा कि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के स्वाभाविक उम्मीदवार घोषणा से पूर्व ही मान लिए गए थे। वे दल के नहीं, सही अर्थों में जनता के प्रधानमंत्री हैं। और कोई अचरज नहीं कि अपने व्यापक अपील एवं लोकप्रियता के बल पर उन्होंने राजनीति को विकास एवं सेवा का माध्यम ही नहीं, पर्याय बना डाला। एक

भारत, श्रेष्ठ भारत, सशक्त भारत के निर्माण के लिए वे पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं। 'स्टैच्यू ऑफ यूनिटी' न केवल सरदार वल्लभभाई पटेल को एक सच्ची श्रद्धांजलि है, अपितु सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों के औज़ार और मिट्टी का उपयोग किए जाने के कारण यह 'एक भारत, श्रेष्ठ भारत' की भावना की जीवंत अभिव्यक्ति है।

राजनीति में उन्होंने कई साहसिक प्रयोग किए जिसे जनता का अपार समर्थन मिला। वे एक ऐसे प्रधानमंत्री के रूप में सामने आए जो केवल शासन-प्रशासन के स्तर पर ही चाक-चौबंद नहीं रखता, अपितु जनसरोकारों से जुड़े लोकहित के छोटे-छोटे मुद्दों पर भी खुलकर अपनी राय रखता है और सरकार की भागीदारी सुनिश्चित करता है। नरेंद्र मोदी से पूर्व शायद ही किसी ने सोचा हो कि कोई प्रधानमंत्री स्वच्छता-अभियान को जन-आंदोलन में परिणत कर सकता है, छोटे-छोटे बच्चे जिसके अभियान के सैनिक और दूत बनकर बड़ों को राह दिखा सकते हैं!

इतना ही नहीं उनके द्वारा प्रारंभ की गई 'प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना' महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक ठोस क़दम साबित हुआ। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना ने गिरते शिशु लिंगानुपात पर रोक लगाई और कन्या भ्रूण हत्या जैसे नृशंस एवं मानवीय कुकृत्य पर अंकुश लगाने में बड़ी सफलता पाई। 'सुकन्या समृद्धि योजना' ने बेटियों को लक्ष्मी एवं शक्ति स्वरूपा मानने की दिशा में समाज को प्रेरित किया।

कोरोना महामारी से उपजी इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने 'सेवा को राजनीतिक गतिविधियों' के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सेवा जिसे आज तक सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, जनकल्याणकारी समितियों का कार्य समझा जाता था, उसे जनतांत्रिक कार्यकर्त्ताओं के गले उतारना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दिशा और दृष्टि, प्रेरणा और पाथेय दोनों की आवश्यकता होती है। सौभाग्य से प्रधानमंत्री जिस विचार-परिवार से आते हैं वहाँ से सेवाव्रती तपोनिष्ठों की कमी नहीं जिनके जीवन का ध्येय ही राष्ट्र-देव की सेवा में स्वयं का अर्पण है।

प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का द्वितीय कार्यकाल भी कई मायनों में ऐतिहासिक एवं उपलब्धिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर अपने मज़बूत इरादे स्पष्ट कर दिए, तीन तलाक के ख़िलाफ़ क़ानून और नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर उन्होंने साफ़ संदेश दिया कि तमाम विरोधों एवं दबावों के बावजूद राष्ट्रहित के मुद्दों पर वे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगें।

जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख के विकास के लिए न केवल अनेकानेक परियोजनाओं पर तेज़ी से काम किया जा रहा है, बल्कि घाटी में लोकतंत्र की बहाली के लिए भी प्रयास जोरों पर है। अब वहाँ के किशोरों एवं युवाओं के हाथों में पत्थर नहीं, क़िताब-कॉपी-कलम हैं। सत्ता पर तालिबान के कब्ज़े के बाद बड़ी संख्या में भारत आए सिख शरणार्थियों ने नागरिकता संशोधन क़ानून के औचित्य को भी प्रमाणित किया है। राम-मंदिर के शिलान्यास एवं भूमि-पूजन कार्यक्रम में जाकर उन्होंने उसका विरोध कर रहे तमाम दलों एवं नेताओं को साफ़-साफ़ संदेश दिया कि राम-मंदिर उनकी पार्टी के लिए केवल एक चुनावी नहीं, अपितु सुदीर्ध-सुविचारित चिंतन से निःसृत सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीय मुद्दा रहा है और उसे लेकर वे या उनकी सरकार किसी भ्रम या द्वंद्व की शिकार नहीं है। उनकी सरकार विचारधारा से जुड़े मुद्दों पर प्रतिबद्धता से काम करने के साथ-साथ महात्मा गाँधी और संघ समर्थित स्वदेशी आधारित अर्थव्यवस्था की दिशा में भी तत्परता से काम करती दिख रही है। 'आत्मनिर्भर भारत' एवं 'लोकल के लिए वोकल' का उनका विचार केवल नारों तक सीमित नहीं दिख रहा। वे इस दिशा में बड़े सधे हुए क़दम बढ़ा रहे हैं। तमाम चीनी ऐप पर प्रतिबंध और चीन के साथ किए गए विभिन्न व्यापारिक समझौतों की समीक्षा एवं उनमें से कुछ का रद्दीकरण उसी दिशा में उठाया गया एक ठोस कदम है। इतना ही नहीं, विभिन्न स्रोतों से छन-छनकर आ रही खबरों के अनुसार लद्दाख में पहली बार भारत सीमा पर मज़बूती से सीना ताने डटकर खड़ा है और चीनी सेना से आँखें मिलाकर बात कर रहा है। गलवान घाटी में भी भारत ने चीन को माक़ूल जवाब दिया था। 'सर्जिकल स्ट्राइक', 'एयर स्ट्राइक' ने स्पष्ट संदेश दिया कि राष्ट्र की एकता, अखंडता एवं सुरक्षा-संप्रभुता से उनकी सरकार कोई समझौता नहीं कर सकती।

बीते डेढ़ वर्ष से ज़ारी इस विकट कोरोना-काल में भी वे और उनकी सरकार जिस दृढ़ता से विभिन्न मोर्चों पर मुस्तैद और तैनात दिखाई देती है, वह उम्मीद की रोशनी बनकर जनता का हौसला बढ़ाती है। नकारात्मक सोच वाले प्रलय के भविष्यवक्ताओं की प्रतिक्रियाओं को यदि कुछ पल के लिए भुला दें तो ऐसा कौन होगा जो यह कहे कि प्रधानमंत्री ने कोरोना से उत्पन्न चुनौतियों से निपटने एवं उसकी रोकथाम में कोई कोर-कसर बाक़ी रखी? 75 करोड़ से अधिक नागरिकों को कोविड का टीका लग जाना क्या कोई छोटी-मोटी उपलब्धि है। इस संकट-काल में भी उन्होंने अपनी स्वतःस्फूर्त सक्रियता, सजगता, सतर्कता, दूरदर्शिता त्वरित निर्णय एवं प्रत्युत्पन्नमति से शासन-व्यवस्था को गति दी, नौकरशाही एवं सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रेरित-प्रोत्साहित किया, यहाँ तक कि विभिन्न मुख्यमंत्रियों से भी

ताल-मेल बनाए रखकर उन्हें भी सार्थक एवं सम्यक दिशा देने का प्रयास किया।

'ब्रू रियांग समझौता, बोडो समझौता, अटल टनल का निर्माण, स्वामित्व योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, कृषि सिंचाई योजना, किसान सम्मान-निधि, प्रधानमंत्री जन धन योजना, सौभाग्य योजना, उजाला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, मुद्रा योजना, जल जीवन मिशन, मेक इन इंडिया, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, वैक्सीन मैत्री, आत्मनिर्भर भारत अभियान, नई एवं राष्ट्रीय शिक्षा नीति आदि उल्लेखनीय योजनाओं एवं उपलब्धियों का श्रेय उन्हें और उनकी सरकार को निश्चित दिया जाना चाहिए।

उनकी बातों, कार्यों एवं योजनाओं में गाँव, गरीब, किसान, वंचित, शोषित जनों का ज़िक्र बार-बार आना अकारण नहीं है। बल्कि वे उनके हितों के लिए प्राणार्पण से प्रयास करते हुए प्रतीत होते हैं। वे एक ऐसे नेता हैं जो संघर्षों की रपटीली राहों पर चलकर और अनुभव की आँच में तपकर केंद्रीय सत्ता के शिखर-पुरुष बने हैं। अच्छी बात यह है कि ग़रीबी की पीड़ा उन्होंने न केवल देखी और सुनी है, अपितु भोगी भी है। इसलिए उन्होंने अपने जीवन का कण-कण और आयु का क्षण-क्षण देश-सेवा के लिए अर्पित कर रखा है। जब वे कहते हैं कि राजनीति उनके लिए सत्ता व सुविधा की मंजिल नहीं, सेवा का माध्यम रही है तो उनका यह वक्तव्य अतिरेकी या अविश्वसनीय नहीं लगता। लोगों को लगता है कि उन्होंने लिया बहुत कम है और दिया बहुत ज़्यादा है। राजनीति में परिश्रम, पुरुषार्थ, त्याग और सेवा का जैसा दुर्लभ दृष्टांत उन्होंने स्थापित किया है, वह उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं और अधिकांश देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। क्या आज से पूर्व भारत में किसी ने सोचा होगा कि हमारे सांसद कोरोना से उत्पन्न विषम एवं संकटकालीन परिस्थितियों से निपटने के लिए अपने वेतन-भत्ते-सुविधाओं में कटौती का आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करेंगें? क्या ऐसे प्रस्तावों को पारित और स्वीकृत कराने की पहल और परिकल्पना राजनीति में आए परिवर्तन की परिचायक नहीं? आज से पूर्व कितने ऐसे प्रधानमंत्री हुए जिनके परिचित-परिजन सत्ता की मलाई के हिस्सेदार नहीं रहे? क्या यह सच नहीं कि राजनीति में वंशवाद के चलन पर प्रधानमंत्री एवं उनके दल ने न्यूनाधिक अंकुश लगा रखा है?

कोरोना महामारी से उपजी इन परिस्थितियों में प्रधानमंत्री ने 'सेवा को राजनीतिक गतिविधियों' के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। सेवा जिसे आज तक सामाजिक संगठनों, धार्मिक संस्थाओं, जनकल्याणकारी समितियों का कार्य समझा जाता था, उसे जनतांत्रिक कार्यकर्त्ताओं के गले उतारना इतना आसान नहीं था। इसके लिए दिशा और दृष्टि, प्रेरणा और पाथेय दोनों की आवश्यकता होती है।

प्रधानमंत्री मोदी का अब तक का द्वितीय कार्यकाल भी कई मायनों में ऐतिहासिक एवं उपलब्धिपूर्ण रहा। उन्होंने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले साल में ही जम्मू-कश्मीर से धारा 370 समाप्त कर अपने मज़बूत इरादे स्पष्ट कर दिए, तीन तलाक के ख़िलाफ़ क़ानून और नागरिकता संशोधन विधेयक पारित कर उन्होंने साफ़ संदेश दिया कि तमाम विरोधों एवं दबावों के बावजूद राष्ट्रहित के मुद्दों पर वे किसी प्रकार का समझौता नहीं करेंगें।

सौभाग्य से प्रधानमंत्री जिस विचार-परिवार से आते हैं वहाँ से सेवाव्रती तपोनिष्ठों की कमी नहीं जिनके जीवन का ध्येय ही राष्ट्र-देव की सेवा में स्वयं का अर्पण है। स्वामी विवेकानंद और महात्मा गाँधी जैसे दृष्टिसंपन्न महापुरूषों से लेकर संघ-परिवार से जुड़े हजारों सेवाव्रती प्रचारकों ने सेवा-कार्य को महत्ता प्रदान की है। 'सेवा भारती' के माध्यम से संघ ने सदैव प्राकृतिक आपदाओं से लेकर वंचितों-शोषितों की सेवा में मन-प्राण लगाए हैं। स्वाभाविक है कि अपने मातृ संगठन की प्रेरणा से इस कोरोना-काल में भाजपा के हजारों-लाखों कार्यकर्त्ताओं ने भी अपनी जान की परवाह न करते हुए दुःखियों-पीड़ितों-प्रवासियों की निःस्वार्थ सेवा की है। और प्रधानमंत्री ने सेवा के लिए अपने दल के लाखों-करोड़ों कार्यकर्त्ताओं को पल-पल प्रेरित-उत्साहित किया है| एक आँकड़े के अनुसार प्रथम लॉकडाउन के दौरान भाजपा कार्यकर्त्ताओं ने लगभग 22 करोड़ से अधिक फूड पैकेट्स एवं 5 करोड़ से अधिक राशन किट्स का वितरण किया। इसके अलावा पार्टी कार्यकर्ताओं ने 5 करोड़ से अधिक फेसकवर्स भी जरूरतमंदों तक पहुँचाए। और 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जब अपने जीवन के 71 वर्ष पूरा करने जा रहे हैं तो पिछले वर्ष की भाँति इस वर्ष भी भाजपा ने इसे सेवा-सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय किया है जो निश्चय ही इस कोरोना-काल में एक सराहनीय क़दम है। पार्टी की योजना इसके अंतर्गत वृक्षारोपण, ब्लड डोनेशन एवं स्वच्छता-कार्यक्रम आयोजित करने की है। इसके अंतर्गत पार्टी हर जिले में 70 जगहों पर सेवा-कार्य संपन्न करेगी। उल्लेखनीय है कि कोई भी दल केवल औपचारिक कार्यक्रमों के ज़रिए जनता के हृदय में स्थाई स्थान नहीं बना सकती, उसे सचमुच ज़मीन पर काम करना होगा और लोगों का, गाँव-ग़रीब-किसान का दिल जीतना होगा। आपदाओं और विपदाओं के इस संक्रमण-काल में सभी राजनीतिक दल सेवा को सत्ता तक पहुँचने या सत्ता में बने रहने का माध्यम बनाएँ तो सचमुच भारत की राजनीति में यह एक सुधारात्मक एवं सकारात्मक बदलाव सिद्ध होगा।

(लेखक शिक्षा-प्रशासक एवं वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी: उनकी बातों में है माटी की महक

संजय द्विवेदी

भारत जैसे महादेश को संबोधित करना आसान नहीं है। इस विविधता भरे देश में वाक् चातुर्य से भरे विद्वानों, राजनेताओं, प्रवचनकारों और अदीबों की कमी नहीं है। अपनी वाणी से सम्मोहित कर लेने वाले अनेक विद्वानों को हमने सुना और परखा है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क्षमताएं उनमें विलक्षण हैं। वे हमारे समय के अप्रतिम संचारकर्ता हैं। संचार का विद्यार्थी होने के नाते मैं उनकी तरफ बहुत विश्लेषणात्मक दृष्टि से देखता हूं, किंतु वे अपनी देहभाषा, भाव-भंगिमा, शब्दावली और वाक् चातुर्य से जो करते हैं, उसमें कमियां ढूंढ पाना मुश्किल है। उनका आत्मविश्वास और शैली तो विलक्षण है ही, वे जो कहते हैं उस बात पर भी सहज विश्वास करने का मन होता है। मोदी सही मायने में संवाद के महारथी हैं। वे जनसभाओं के नायक हैं तो ट्विटर जैसे नए माध्यमों पर भी उनकी तूती बोलती है। पारंपरिक मंचों से लेकर आधुनिक सोशल मीडिया मंचों पर उनकी धमाकेदार उपस्थिति बताती है संवाद और संचार को वे किस बेहतर अंदाज में समझते हैं।

गुजरात के एक छोटे से कस्बे बड़नगर में पले-बढ़े नरेंद्र मोदी में ऐसा क्या है जो लोंगों को सम्मोहित करता है? उनकी राजनीतिक यात्रा भी विवादों से परे नहीं रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में उन्हें जिस तरह निशाना बनाकर उनकी छवि मलिन करने के सचेतन प्रयास हुए, वे सारे प्रसंग लोकविमर्श में हैं। बावजूद इसके वे हिंदुस्तानी समाज के नायक बने हुए हैं तो इसके पीछे उनकी संप्रेषण कला और देहभाषा का अध्ययन प्रासंगिक हो जाता है। नरेंद्र मोदी देश के ऐसे प्रधानमंत्री हैं, जो कभी सांसद नहीं थे और पहली बार लोकसभा पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री बने।

2014 के आमचुनावों की याद करें तो देश किस तरह निराशा और अवसाद से भरा हुआ था। लोग राजनीति और राजनेताओं से उम्मादें छोड़ चुके थे। अन्ना आंदोलन से एक अलग तरह का गुस्सा लोगों के मन में पनप रहा था। तभी एक आवाज गूंजती है 'मैं देश नहीं झुकने दूंगा।' दूसरी आवाज थी 'अच्छे दिन आने वाले हैं।' ये दो आवाजें थीं नरेंद्र मोदी की, जो देश को एक विकल्प देने के लिए मैदान में थे। राजनीति में आश्वासनपरक आवाजों का बहुत मतलब नहीं होता, क्योंकि राजनीति तो सपनों और

नरेंद्र मोदी अपनी असंदिग्ध ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित है। ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपकी वाणी को आपके जीवन का समर्थन है। सिर्फ देश की बात करना और देश के लिए जीना दो बातें हैं। मुझे लगता है जीवन और कर्म में एक रूप होने के नाते मोदी बाकी राजनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर सबको भरोसा है, इसलिए उनकी वाणी पर भी सहज विश्वास आता है। इस तरह उनकी वाणी 'भाषण' न होकर 'ह्दय से ह्दय के संवाद' में बदल जाती है। लोंगों को भरोसा है कि वे हमारी ही बात कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं।

आश्वासनों के आधार पर ही की जाती है। किंतु नरेंद्र मोदी ने इस दौर में जो कुछ कहा उसे देश ने बहुत ध्यान से सुना। उनका दल लंबे समय से सत्ता से बाहर था और वे अपने दल की ओर से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाए जा चुके थे। जाहिर है अवसाद और निराशा से भरी जनता को एक अवसर था परख करने का। मोदी इस अवसर का लाभ उठाते हैं और जनता के मन में भरोसा जगाने का प्रयास करते हैं। वे लगातार अपनी सभाओं में कहते हैं कि वे ही इस देश को उसके संकटों से उबार सकने की क्षमता से लैस हैं। जनता मुग्ध होकर उनके भाषणों को सुनती है। अपनी अप्रतिम संवादकला से वे लोगों में यह भरोसा जगाने में सफल हो जाते हैं कि वे कुछ कर सकते हैं।

2014 में मोदी सत्ता में आते हैं और संचार के सबसे प्रभावकारी माध्यम को साधते हैं। वे आकाशवाणी पर 'मन की बात' के माध्यम से लोगों से संवाद का अवसर चुनते हैं। यानि उनका संवाद अवसर और चुनाव केंद्रित नहीं है, निरंतर है। उनमें एक सातत्य है। बदलाव के लिए, परिवर्तन के लिए, लोकजागरण के लिए। वे मन की बात को राजनीतिक विमर्शों के बजाए लोकविमर्शों का केंद्र बनाते हैं। जिसमें जिंदगी की बात है, सफाई की बात है, शिक्षा और परीक्षा की बात है, योग की बात है। मन की बात के माध्यम से वे खुद को एक ऐसे अभिभावक की तरह पेश करने में सफल होते हैं, जिसे देश और देशवासियों की चिंता है। संवाद की यही सफलता है और यही उसका उद्देश्य है। अपने लक्ष्य समूह को निरंतर अपने साथ जोड़े रखना मोदी की संवाद कला की दूसरी सफलता है। करोना संकट में भी हमने देखा कि उनकी अपीलों को किस तरह जनमानस ने स्वीकार किया, चाहे वे करोना वारियर्स के सम्मान में दीप जलाने और थाली बजाने की ही क्यों न हों। यह बातें बताती हैं कि अपने नायक पर देश का भरोसा किस तरह कायम है।

मोदी अपनी देहभाषा से कमाल करते हैं। कई बार चौंकाते भी हैं। देश की गहरी समझ भी इसका बड़ा कारण है, यही कारण है वे देश के जिस हिस्से में होते हैं वहां की स्थानीय बोली, वस्त्रों और प्रतीकों का सचेत इस्तेमाल करते हैं। इसके साथ ही उनकी पोशाकें, उनका हाफ कुर्ता, जैकेट्स आज एक तरह से स्टाइल स्टेटमेंट है। उनका अनुसरण कर नौजवान आज खद्दर और सूती कपड़ों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं। हम विश्लेषण करें तो पाते हैं कि उनका समर्पित जीवन और ईमानदारी से उनकी वाणी का भी एक रिश्ता है। जब हम सिर्फ बोलते हैं तो उसका असर अलग होता है। किंतु अगर हम जो बोलते हैं उसमें कृतित्व भी शामिल हो तो बात का असर बढ़ जाता है।

नरेंद्र मोदी अपनी असंदिग्ध ईमानदारी, राष्ट्रनिष्ठा और देशभक्ति के प्रतीक हैं। उनका समूचा जीवन राष्ट्र के लिए अर्पित है। ऐसा व्यक्ति जब कोई बात कहता है तो उसका असर बहुत ज्यादा होता है। क्योंकि आपकी वाणी को आपके जीवन का समर्थन है। सिर्फ देश की बात करना और देश के लिए जीना दो बातें हैं। मुझे लगता है जीवन और कर्म में एक रूप होने के नाते मोदी बाकी राजनेताओं से बहुत आगे निकल जाते हैं। क्योंकि उनकी राष्ट्रनिष्ठा पर सबको भरोसा है, इसलिए उनकी वाणी पर भी सहज विश्वास आता है। इस तरह उनकी वाणी 'भाषण' न होकर 'ह्दय से ह्दय के संवाद' में बदल जाती है। लोंगों को भरोसा है कि वे हमारी ही बात कर रहे हैं और हमारे लिए ही कर रहे हैं। मोदी ने अपनी साधारण पृष्ठभूमि की बात कभी छिपाई नहीं, जब भी उनकी साधारण स्थितियों का मजाक बनाया गया तो उसे भी उन्होंने एक सफल अभियान में बदल दिया। 'चाय पर चर्चा' का कार्यक्रम किस तरह बना, उसके संदर्भ हम सबके ध्यान में हैं।

नरेंद्र मोदी सही मायने में सामान्य जनों में भरोसा जगाते हैं कि अगर संकल्प हों, इच्छाशक्ति हो तो व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। यह एक बात लोगों को उनसे कनेक्ट करती है। अनेक राजनेता हैं, जो साधारण पृष्ठभूमि से आए हैं। किंतु उनका या तो अपनी जड़ों से उनका रिश्ता टूट गया है या वे उन विथिकाओं को याद नहीं करना चाहते। जबकि नरेंद्र मोदी अपनी जड़ों को नहीं भूलते वे हमेशा उसे याद करते हैं और खुद पर भरोसा करते हैं। यही कारण है उनका कनेक्ट सीधा जनता से बनता है। वे प्रधानमंत्री होकर भी अपने से नजर आते हैं। संचार, संवाद और पोजिशिनिंग की यह कला उनमें सहज है। बिना जतन के भी वे इन सबको साधते हैं और साधते रहेंगें क्योंकि आसमान पर होकर भी माटी की सोंधी महक उन्हें जड़ों से जोड़े रखती है। इसलिए उनका संवाद दिलों को जोड़ता है, देश को भी।

(लेखक भारतीय जन संचार संस्थान नई दिल्ली के महानिदेशक हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

बेमिसाल बीस वर्ष

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

नरेंद्र मोदी बीस वर्षों से संवैधानिक पद पर है। वह सात वर्षो से वह प्रधानमंत्री है, उसके पहले वह गुजरात के मुख्यमंत्री थे। इन दो दशकों में उन्होंने एक भी अवकाश नहीं लिया। वह अपने जन्म दिन पर औपचारिकता से दूर रहते है,पहले जब समय मिलता था तो अपनी माँ का आशीर्वाद लेने जाते थे। होली दीपावली जैसे त्योहार वह सैनिकों के बीच मनाते है। इन दिनों में भी वह शेष समय में सरकारी कार्य जारी रखते है। उनका जीवन राष्ट्र के प्रति समर्पित है। परिजनों ने इस बात को मन से स्वीकार कर लिया था। मोदी ने भी समाज सेवा व्रत का पूरी मर्यादा से पालन किया। कुछ तो ऐसा है कि गुजरात से लेकर आज तक विरोधी उनकी बराबरी करने में विफल रहे। मोदी लगातार आगे बढ़ते रहे, विरोधी उनके मुकाबले पीछे छूटते गए। इसका कारण नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की नेकनीयत है,इसके बल पर आमजन के बीच उनकी विश्वसनीयता कायम है। लोगों को विश्वास है कि मोदी देश व समाज के प्रति समर्पित है। वह पूरे देश को अपना परिवार मानकर समर्पित भाव से सतत सक्रिय है। डिजिटल इंडिया,स्किल इंडिया,मेक इन इंडिया, स्टार्ट अप,स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री जन-धन योजना,मुद्रा योजना, फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना,प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना और सागर माला, भारत माला नमामि गंगे परियोजना आदि की अभूतपूर्व उपलब्धि उनकी नेकनीयत के ही प्रमाण है। राजीव गांधी ने कहा था कि दिल्ली से भेजे गए सौ पैसे में गरीबों तक मात्र पन्द्रह पैसे पहुंचते है। मोदी ने ऐसा कर दिया कि अब शतप्रतिशत धन गरीबों के बैंक खाते में पहुंचने लगे। दूसरे कार्यकाल की शुरुआत में ही अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल हुई है। श्री रामजन्म भूमि पर मंदिर निर्माण हेतु भूमिपूजन हुआ। इसके पहले अनुच्छेद तीन सौ सत्तर,पैतीस ए और तीन तलाक की समाप्ति हुई। नागरिकता संशोधन कानून लागू हुआ। यह सब नरेंद्र मोदी की दृढ़ता से संभव हुआ। कोरोना संकट ने आर्थिक गतिविधियों को सीमित किया है। इसका प्रतिकूल प्रभाव अर्थव्यवस्था पर पड़ना ही था। लेकिन यह समस्या केवल भारत तक सीमित नहीं है।

दुनिया के सभी देशों में जीडीपी का ग्राफ नीचे आया है। ऐसे में केवल भारत का उल्लेख करना निराश करने वाला है। परिस्थियों के अनुरूप ही आकलन होना चाहिए। लेकिन कुक लोग वर्तमान समय की तुलना पिछली यूपीए सरकार से कर रहे है। वह कोरोना के समय आई गिरावट पर फोकस करते

है। यह संकट स्थाई नहीं है। इसमें भी नरेंद्र मोदी सरकार ने अबतक का सबसे बड़ा आर्थिक पैकेज दिया है। ऐसे में यूपीए सरकार से तुलना इस समय बेमानी है। कार्यशैली और घोटालों के मामले में मनमोहन सिंह व मोदी सरकार के बीच जमीन आसमान का अन्तर है। इस तथ्य को देश का आम जनमानस भी स्वीकार करता है। यह ठीक है कि देश में आज भी बहुत समस्याएं हैं। वर्तमान सरकार की नीयत पर आमजन को विश्वास है। यह माना जा रहा है कि सरकार सही दिशा में आगे बढ़ रही है। यूरिया खाद की उपलब्धता, फसल बीमा को व्यापक रूप में लागू करना, सिंचाई, बिजली आदि की रैंकिंग में आगे निकलना,मेक इन इंडिया,स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया आदि के दूरगामी परिणाम देखने को मिलेंगे। देश पुनः तेज दर से विकास करेगा। भारत की अर्थव्यवस्था पर दुनिया का भरोसा बढ़ा है। मोदी सरकार ने अपने कार्यकाल में अनेक महत्वपूर्ण योजनाएं लागू की ही हैं। साथ ही पिछली सप्रंग सरकार के समय शुरू की गयी कई अनेक योजनाओं को भी आगे बढ़ाया है। इनकी गति व स्वरूप से दोनों सरकारों के बीच का अन्तर आसानी से समझा जा सकता है।

योजनाएं बनाने में सप्रंग सरकार भी कम नहीं थी। लेकिन क्रियान्वयन के स्तर पर उसका प्रदर्शन दयनीय रहा। उनकी गति बहुत धीमी थी। इसके अलावा घोटालों की वजह से भी अनेक योजनाएं विफल साबित हुई थीं। बड़ी संख्या में परियोजनाओं पर कार्य तो शुरू हुआ लेकिन कुछ समय बाद उनको रोक दिया गया। ऐसी परियोजनाएं वर्तमान सरकार को विरासत में मिली हैं। इनकी लागत भी बहुत बढ़ चुकी थी। इस आधार पर दो प्रमुख निष्कर्षों का उल्लेख किया जा सकता है। एक यह कि मोदी सरकार ने कार्यशैली में बहुत बदलाव किया है। इसके पीछे प्रधानमंत्री के नेतृत्व का भी प्रभाव है। इस कारण क्रियान्वयन पक्ष मजबूत हुआ है। दूसरा यह कि मोदी सरकार भ्रष्टाचार व घोटालों से मुक्त रही है।

कोरोना से पहले दुनिया में भारत तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के रूप में प्रतिष्ठित हो चुका था। विश्व के थिंक टैंक व आर्थिक विशेषज्ञ भी इस तथ्य को स्वीकार करने लगे थे। दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था चीन की थी। लेकिन भारत उसके सामने चुनौती बनकर उभर रहा है। चीन के रणनीतिक थिंक टैंक एन बाउंड ने यह विश्लेषण प्रस्तुत किया था। इसके अनुसार चीन पिछड़ रहा है। उसने जवाबी रणनीति नहीं बनाई तो वह भारतीय सफलता का तमाशबीन बनकर रह जाऐगा। चीन ने भारत का पर्याप्त अध्ययन नहीं किया है। सच्चाई यह है कि मोदी सरकार में बहुत कुछ बदल रहा है। जो बदलाव भारत में हो रहे हैं वे विकास की बड़ी संभावना की ओर इशारा करते हैं। भारत में उभरते हुए बाजार की संभावना भी अधिक है और निवेशक उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। यह भी बताया जा रहा है कि चीन की अर्थव्यवस्था ढलान पर है। भारत उसकी जगह ले सकता है। चीन का कर्ज

विदेश नीति को भी मोदी सरकार ने प्रभावी बनाया है। अनेक देशों के साथ सहयोग के नए अध्याय शुरू हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा व बौद्ध धर्म के माध्यम से अलग अलग समूह बनाने का जो प्रयास किया है,उसका दूरगामी प्रभाव होगा। विश्व के बीस से अधिक देशों में बौद्ध धर्म है। इनका भारत के प्रति स्वाभाविक लगाव है। इनके साथ साझा मंच बनाने से भारत को वैश्विक मामलों में सहयोग मिलेगा। इनके बीच आपसी सहयोग बढ़ने का आर्थिक व पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से भी अनेक देशों का साझा मंच आकार ले रहा है। इसकी कल्पना मोदी ने की थी। इस देशों में सूर्य देव की अधिक कृपा होती है। इससे ऊर्जा निर्माण की बड़ी संभावना है। यह प्रयास सार्थक हुए तो भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। वहीं इन सभी देशों के बीच साझा संबंध आगे बढ़ेंगे जिनका सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। यह सही है कि पाकिस्तान सीमा पर तनाव कायम है।

उसके जीडीपी का दो सौ साठ प्रतिशत हो गया है। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने इसे लेकर उसे चेतावनी भी दी है। बढ़ते कर्ज को कम नहीं किया गया तो चीन की अर्थव्यवस्था धड़ाम हो जाएगी। अर्थात उसे मुंह के बल गिरने से कोई रोक नहीं सकेगा। इसी लिए वह बौखला रहा है।

करीब तीन वर्ष पहले विश्व बैंक की भारत के संबंध में अनुकूल रिपोर्ट थी। इसके अनुसार वैश्विक आर्थिक सुस्ती के बावजूद भारत की विकास दर सात प्रतिशत पर बनी हुई थी। कोरोना संकट के बाद यह सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। केन्द्र सरकार ने विभिन्न क्षेत्रों में विकास की व्यापक योजनाएं बनाई हैं। लेकिन इनका लाभ उन्हीं राज्यों को ज्यादा मिलेगा,जो खुद सजग व तत्पर होंगे। उन्हें सहयोगी संघवाद की भावना से काम करना होगा। विकास के मामले में दलगत सीमा से ऊपर उठना होगा। उत्तर प्रदेश की पिछली सरकार कृषि क्षेत्र में केंद्र से मिली धनराशि का मात्र पचास प्रतिशत ही खर्च कर पाती थी। केंद्र सरकार की कृषि बाजार योजना को भी ठीक से लागू करने का प्रयास नहीं किया गया। इसी प्रकार प्रदेश में पिछली सरकारों ने कृषि विज्ञान केंद्र नहीं खोले थे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बीस कृषि विज्ञान केंद्र खोलने की दिशा में कदम भी बढ़ा दिए हैं। बुन्देलखंड में तीन हजार से ज्यादा खेत तालाबों का निर्माण सुनिश्चित हुआ। हर घर नल से जल योजना आगे बढ़ रही है। केंद्र सरकार ने सार्वजनिक उपक्रमों के संबंध में भी कारगर नीति बनाई थी। नीति आयोग खुद इस दिशा में पहल कर रहा था। कुछ को छोड़ दें तो अन्य सार्वजनिक उपक्रम घाटे में चल रहे हैं। जाहिर है कि राज्य सरकारों को

इस दिशा में प्रयास करने होंगे। नीति आयोग ने कहा भी है कि जो सार्वजनिक उपक्रम लगातार घाटे में चल रहे हैं, जिनमें सुधार की ज्यादा संभावना नहीं है, उन्हें निजी क्षेत्र को देने पर विचार करना चाहिए। सरकारी व्यय में लीकेज रोकने का काम भी राज्यों को करना है। जहां तक केन्द्र का प्रश्न है,मोदी सरकार की ओर से सब्सिडी सीधे खातों में भेजने मात्र से हजारों करोड़ का लीकेज रूका है। नीम कोटेड यूरिया ने भी बड़े घोटाले को रोका है। स्पेक्ट्रम,कोयला ब्लॉक आवंटन में पारदर्शिता ने सरकारी राजस्व सुनिश्चित किया है। इस सब मामलों में पहले क्या होता था,यह बताने की जरूरत नहीं। ऐसा लगता था जैसे सरकारी धन में लीकेज के इंतजाम सत्ता में बैठे लोगों ने ही किए थे। इनको रोकने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी।

विदेश नीति को भी मोदी सरकार ने प्रभावी बनाया है। अनेक देशों के साथ सहयोग के नए अध्याय शुरू हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने सौर ऊर्जा व बौद्ध धर्म के माध्यम से अलग अलग समूह बनाने का जो प्रयास किया है,उसका दूरगामी प्रभाव होगा। विश्व के बीस से अधिक देशों में बौद्ध धर्म है। इनका भारत के प्रति स्वाभाविक लगाव है। इनके साथ साझा मंच बनाने से भारत को वैश्विक मामलों में सहयोग मिलेगा। इनके बीच आपसी सहयोग बढ़ने का आर्थिक व पर्यटन के क्षेत्र में बड़ा लाभ होगा। सौर ऊर्जा के माध्यम से भी अनेक देशों का साझा मंच आकार ले रहा है। इसकी कल्पना मोदी ने की थी। इस देशों में सूर्य देव की अधिक कृपा होती है। इससे ऊर्जा निर्माण की बड़ी संभावना है। यह प्रयास सार्थक हुए तो भविष्य की ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। वहीं इन सभी देशों के बीच साझा संबंध आगे बढ़ेंगे जिनका सकारात्मक प्रभाव अन्य क्षेत्रों में भी दिखाई देगा। यह सही है कि पाकिस्तान सीमा पर तनाव कायम है।

चीन के साथ उसका गठजोड़ भारत के लिए परेशानी का कारण है। भारत की सीमाएं सुरक्षित होनी चाहिए। भारतीय सेना चीन को जबाब दे रही है। कुछ लोग इस प्रकार आलोचना कर रहे है जैसे चीन व पाकिस्तान से तीन वर्ष पहले हमारे बड़े अच्छे रिश्ते थे। अब बिगड़ गए। मोदी ने रिश्ते सुधारने के प्रयास किए। विदेश नीति में अनेक तथ्य शामिल होते हैं। कई बार अपेक्षित परिणाम नहीं मिलते। फिर भी यह नहीं भूलना चाहिए कि दोनों देशों के साथ बड़े युद्ध के बावजूद समझौते करने पड़े थे। संप्रग सरकार ने रक्षा क्षेत्र की तैयारियों में भी लापरवाही दिखाई थी। मोदी सरकार इस दिशा में कमियों को पूरा करने का प्रयास कर रही है। कुछ तो है जो पाकिस्तान इन तीन वर्षों में कई बार संयुक्त राष्ट्रसंघ में भारत की शिकायत लेकर दौड़ा है। उसे मुंहतोड़ जवाब मिल रहा है। जाहिर है मोदी सरकार नेक नीयत के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह कर रही है।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार मोदी

अरविंद जयतिलक

सात वर्ष के ऐतिहासिक कालखंड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहां एक ओर अपनी सफल कुटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रुस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है। किसी भी राष्ट्र की विदेशनीति को प्रभावित करना अथवा अपने अनुकूल बनाना आसान नहीं होता। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने यह कमाल कर दिखाया है।

पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, उर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान की यात्रा की। तब उन्होंने 'भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत' की जरुरत बता दोनों देशों के अटूट रिश्तों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने भूटानी संसद के माध्यम से भूटान को भरोसा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। 2019 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली तब बिम्सटेक देशों के नेताओं को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया और उसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के छोटे भाई सरीखे नेपाल के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है। उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकदुलारी मां सीता की पावन जन्मस्थली जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में दर्शन-पूजन कर दोनों देशों की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की पहल की। तब उन्होंने कहा था कि वह बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य तीर्थयात्री बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल से निकला यह उद्गार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि नेपाल भारत के दिल में बसता है और भारत उसके सुख-दुख का साथी है।

प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक-सांस्कृतिक संबंधों

से इतर दोनों देशों की उन्नति के लिए एक नई परिकल्पना '5-टी' यानी 'ट्रेडिशन (परंपरा), ट्रेड (व्यापार), टूरिज्म (पर्यटन), टेक्नोलॉजी (तकनीक), और ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के क्षेत्र में मिलकर काम करने की वकालत की और नेपाल ने भी सहमति जतायी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का भी दिल जीता है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिल रही है। पड़ोसी देशों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मध्य एशिया और यूरोप से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, उर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुटनीति से मध्य एशिया के देशों से व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में भारत को पैठ बनाने में मजबूती मिलेगी।

मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के कुटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर ऑफ़ जायद' से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तब प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया था और 'अपने दूसरे घर' आने के लिए आभार जताया। तब प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में व्यापार जगत के प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद स्पष्ट किया और साथ ही भारतीय रुपे कार्ड को भी लांच किया। इस तरह पश्चिम एशिया में यूएई पहला देश बन गया जहां रुपे कार्ड चलता है। सऊदी अरब से भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। याद होगा पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलाने की भारत की मुहिम को दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के बीच फरवरी 2019 में भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज ने भी भारत के साथ कंधा जोड़ने का वादा किया। जबकि यह सच्चाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी निकटता है। वैश्विक मसलों पर अमूमन दोनों का सुर एक जैसा रहता है। लेकिन इसके बावजूद भी सऊदी अरब का आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती महत्ता और सकारात्मक कुटनीतिक विजय का ही नतीजा है।

पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, उर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री मोदी की कुटनीतिक पहल से मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, कजाकिस्तान, कतर, मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जार्डन सरीखे अन्य मुस्लिम देशों से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है। दोनों देशों के रिश्ते को स्वर्ग में बनने और धरती पर लागू करने के भावुक विचार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि दोनों देश भावनात्मक रुप से एकदूसरे के कितने निकट हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं। भारत और यूरोपीय संघ 'स्टैंड-अलोन' निवेश संरक्षण पर सहमति के साथ साझा हितों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान जैसे कई अन्य मानवीय मसलों पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि यह हमारी सामरिक साझेदारी का मूल्य है। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ ढांचा 2025 को लेकर तय कार्य बिंदुओं पर आगे बढ़ने तथा टिकाऊ विकास एवं पेरिस समझौता 2030 के एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार है। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुटनीतिक-रणनीतिक धार से दशकों पुराने अमेरिका की पाक नीति को बदलकर रख दिया है। उनकी कुटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा भारत के साथ रक्षा संबंध विकासित करने और रक्षा उपकरणों की बिक्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अन्य नाटो के सहयोगी देशों के साथ लाने की पहल के तहत द्विदलीय समर्थन वाले बिल को मंजूरी दे दी है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुटनीतिक पहल से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरिया बढ़ी है। पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कितनी निकटता थी इसी से समझा जा सकता है कि मई, 1965 में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉनसन के निमंत्रण पर वहां की यात्रा का कार्यक्रम बनाया तब उसी समय पाकिस्तान के अयूब खान के दौरे के कार्यक्रम के कारण अमेरिका ने अपना

निमंत्रण वापस ले लिया। यही नहीं जब भी कभी प्रतिबंधों की बात आयी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी किसी प्रकार की अमेरिकी सहायता प्रदान करने पर रोक लगाया। यानी तब अमेरिका के पलड़े पर भारत और पाकिस्तान बराबर थे। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर अमेरिका को उससे न सिर्फ दूर किया है बल्कि अमेरिकी संसद के जरिए भारत और अमेरिका के अपरिहार्य संबंधों को भी निरुपित कर दिया है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी और एमटीसीआर के मसले पर अमेरिका के समर्थन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मानकर चलना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान को पहले जैसा न तो अमेरिका से करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिलने वाला है और न ही कुटनीतिक समर्थन। मजेदार तथ्य यह भी कि अमेरिका की लाख धौंसपट्टी के बावजूद भी भारत ने रुस के साथ 40 हजार करोड़ रुपए के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरुरत बताकर स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वह किसी के अर्दब में आने वाला नहीं है। यही नहीं भारत ने एस-400 को लेकर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंधों के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए कह भी चुका है कि भारत का रुस के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि भारत अमेरिका या रुस के दबाव में अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला नहीं है।

अभी गत माह पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रुस की विक्ट्री डे परेड उत्सव में भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत किया। उस दरम्यान रुस ने चीन की लाख मनाही के बावजूद भी भारत को एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रतिबद्धता दोहराकर रेखांकित किया कि दोनों देश सदाबहार और भरोसेमंद साथी हैं। गौर करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का रुस और अमेरिका दोनों से रिश्ते प्रगाढ़ है। आमतौर पर भारतीय कालखंड में ऐसा

मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के कुटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'आर्डर ऑफ़ जायद' से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था।

दौर कभी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कुटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बावजूद भी भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार है और जरुरत पड़ने पर अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन्स को खरीद भी सकेगा। अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है। क्योंकि मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कतार में हैं। ध्यान देना होगा कि ये वहीं देश हैं जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की साम्राज्यवादी नीति से परेशान हैं।

भारत-जापान, भारत-जर्मनी, भारत-फ्रांस मजबूत होते रिश्ते और दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग, रक्षा उपकरण तकनीक और गोपनीय सैन्य सूचना संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण समझौते से भी चीन परेशान है। भारत और जापान के एक साथ आने से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लगाम लगा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ़ एग्रीमेंट सप्लाई एग्रीमेंट (एलईएमओ) ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से दोनों देशों के युद्धपोत और फाइटर

प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, उर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है।

एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल तेल भराने एवं अन्य साजो-सामान की आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। इससे चीन खौफजदा है और उसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। चीन इसलिए भी असहज है कि चार देशों के राजनीतिक समूह क्वाड (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलॉग) के सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी रुख अपना रखे चीन पर नकेल कसना शुरु कर दिया है। मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि चीन को अब अपने हद में रहने की जरुरत है। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सात वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है।

(लेखक वरिष्ठ पत्रकार एवं राजनीतिक विश्लेषक हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

महिला सशक्तिकरण को नए आयाम देती मोदी सरकार

डॉ. खुशबू गुप्ता

"महिला – वो शक्ति है, सशक्त है, वो भारत की नारी है, न ज्यादा में, न कम में, वो सब में बराबर की अधिकारी है।" इस संकल्प के साथ मोदी सरकार ने नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर होते हुए देश की विकास प्रक्रिया में आधी आबादी की भागीदारी को सुनिश्चित किया है। वर्तमान में महिलाओं के विकास से सम्बंधित विमर्श बदल चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए भारत में महिलाएं अब न केवल योजनाओं की लाभार्थी हैं बल्कि लैंगिक विषमताओं को पीछे छोड़ते हुए विकास की योजनाओं का नेतृत्व भी कर रही हैं।

संसदीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता, महिलाओं को उचित और समान अवसर प्राप्त होना आदि बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बात की महत्ता को केंद्र में रखकर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कानून व विकासात्मक नीतिओं का निर्माण तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहलें की जाती रही हैं।

विदित हो कि महिला सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय नीति – 2001 को अस्तित्व में आये लगभग दो दशक हो गए हैं। 'इस बीच देश-दुनिया में नई तकनीकी और सूचनातंत्र में आये बदलाव के चलते भारत के सामाजिक, आर्थिक ढाँचे में भी महत्वपूर्ण परिवर्तन आया है। इसी को ध्यान में रखते हुए मोदी सरकार ने एक नई राष्ट्रीय महिला नीति का प्रारूप तैयार किया है।

इस नए प्रारूप में महिला स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, पोषण व शिक्षा पर ध्यान देना; अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों जैसे कृषि उद्योग, श्रम, रोजगार, विज्ञान एवं तकनीकी तथा सेवा क्षेत्र में महिलाओं की सहभागिता और नेतृत्व को बढ़ाना; महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा की रोकथाम करना; प्रशासन एवं नीति निर्माण और अन्य क्षेत्रों जैसे मीडिया, संचार, संस्कृति, खेल कूद और सामाजिक सुरक्षा में महिलाओं की भागीदारी तथा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन में उनकी भूमिका को बढ़ाना प्रमुख है। निश्चित रूप से यह नीति महिलाओं के

जीवन में व्यापक रूप से सकारात्मक बदलाव के द्वार खोलेगी।

गौरतलब है कि अपने पहले कार्यकाल में नरेन्द्र मोदी ने नारी-शक्ति को केंद्र में रखकर 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान की शुरुआत करते हुए अपने इरादों का परिचय दे दिया था। उन्होंने स्पष्ट कर दिया था कि विकास के अभियान में महिलाओं के प्रतिनिधित्व को बढ़ाये बगैर उनकी क्षमता का सही उपयोग नही हो सकता।

बता दें कि मोदी सरकार में लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण, महिला स्वावलंबन जैसे मुद्दों के साथ ही साथ अनेक सामाजिक, आर्थिक योजनाओं जैसे बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ; वित्तीय समावेशन की योजनाएं, मुद्रा योजना, जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण योजना और कौशल विकास जैसी तमाम योजनाओं के केंद्र में महिलाएं पहले से ही रही हैं।

वर्तमान आकड़ों को देखें तो उज्ज्वला योजना के माध्यम से करीब 8 करोड़ भारतीय महिलाओं की एलपीजी गैस सिलिंडर तक पहुँच ने उनको स्वस्थ जीवन जीने के लिए सशक्त किया है। वही उज्जवला 2.0 की बात की जाए तो इसके माध्यम से और 1 करोड़ वंचित परिवारों को लाभार्थी के रूप में शामिल किया गया है।

ध्यान देने योग्य बात यह है कि यह योजना न केवल व्यापक स्तर पर सामाजिक परिवर्तन ला रही है बल्कि इस योजना के अधिकांश लाभार्थी ऐसी महिलाएं हैं जो कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के समुदायों से आती हैं।

संसदीय लोकतंत्र में महिला सशक्तिकरण, लोकतान्त्रिक प्रक्रिया में उनकी सहभागिता, महिलाओं को उचित और समान अवसर प्राप्त होना आदि बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इस बात की महत्ता को केंद्र में रखकर महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के मूलभूत ढांचे के अंतर्गत कानून व विकासात्मक नीतिओं का निर्माण तथा विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों की पहलें की जाती रही हैं।

सामाजिक-आर्थिक क्षेत्र के साथ ही साथ राजनीतिक व्यवस्था में भी महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का पहला मंत्रिपरिषद विस्तार कई मायनो में ऐतिहासिक रहा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण आधी-आबादी या यूं कहें कि महिलाओं के प्रतिनिधित्व में प्रधानमंत्री मोदी का विश्वास रहा जिसके परिणामस्वरुप मंत्रिपरिषद विस्तार में महिला मंत्रियो की कुल संख्या 11 तक पहुच गयी जो कि अब तक

का उच्चतम प्रतिनिधित्व है।

इस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के दूसरे मंत्रिपरिषद के विस्तार ने पिछले सभी कार्यकालों की तुलना में महिलाओं को ज्यादा प्रतिनिधित्व दिया है। इसके अलावा दो मंत्रिपद, जिसमे एक वित्त मंत्रालय जिसका कार्यभार निर्मला सीतारमण संभाल रही हैं जो कि पूर्व में रक्षा मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल चुकी हैं। और दूसरा 'महिला और बाल विकास मंत्रालय' जिसकी ज़िम्मेदारी स्मृति ईरानी के पास है। ये दोनों महिलाएं प्रधानमंत्री मोदी के कैबिनेट में शामिल हैं। इतने महत्वपूर्ण मंत्रालयों का कार्यभार महिला मंत्रियों के कंधे पर डालना नए भारत की महिला शक्ति के प्रति प्रधानमंत्री मोदी के विश्वास को ही दर्शाता है।

यदि समावेशी प्रतिनिधित्व पर ध्यान दिया जाये तो यह स्पष्ट हो जाता है कि प्रधानमंत्री मोदी 'सामाजिक-सहभागिता' और 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' के सपने को साकार रूप दे रहें हैं। महिला मंत्रियो में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़ा वर्ग सहित समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व स्पष्ट दिखाई देता है। एक तरफ जहा अनुप्रिया पटेल उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग से आती हैं, वही पेशे से डॉक्टर भारती पवार अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

मंत्रिपरिषद में प्रतिनिधित्व के अलावा इस सरकार में अधिकतम महिला राज्यपाल भी रही हैं, जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों का कुशल निर्वहन कर रही हैं। महिला राज्यपालों में नजमा हेपतुल्लाह जहां अल्पसंख्यक समुदाय से आती हैं, वही द्रोपदी मुर्मू और अनुसुईया उईके अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व करती हैं।

कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है कि मोदी सरकार ने बिना किसी शोर-शराबे के महिलाओं को केंद्र में ला कर खड़ा किया है, जिसकी शुरुआत 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' अभियान से हुई थी और आज महिलाओं को समुचित प्रतिनिधित्व देकर नये भारत के निर्माण में उनकी भूमिका को स्वीकारा और सराहा जा रहा है। न केवल सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक बल्कि सैन्य और न्यायपालिका जैसे संस्थानों में भी महिलाओं का गरिमामयी प्रतिनिधित्व बढ़ी है।

पाश्चात्य आधारित नारीवाद के अतिरेक से अलग, प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कुशल नेतृत्व और दूरदर्शिता से नारी-शक्ति को मुख्यधारा में लाकर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के उस वाक्य को भी साकार कर दिया है, जिसमें वे कहते थे कि, "किसी भी समाज की प्रगति का मापन महिलाओं की प्रगति से होता है।"

(लेखिका दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

सरकारी योजनाओं से भारत को सशक्त बनाने की पहल

सतीश सिंह

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रधानमंत्री जनधन योजना की मदद से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने, डिजिटल इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने, आमजन को आत्मनिर्भर बनाने आदि का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए बीमा और पेशन योजनाओं को चलाने का काम कर रहे हैं.

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में कई ऐसी योजनाओं का आगाज किया है, जिनकी मदद से अर्थव्यवस्था भी मजबूत हो रही है और बड़ी संख्या में आम आदमी भी लाभान्वित हो रहे हैं. इन योजनाओं में से प्रधानमंत्री जनधन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना आदि का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है.

प्रधानमंत्री जनधन योजना

"प्रधानमंत्री जनधन योजना" मोदी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जो पूर्व के "स्वाभिमान" नामक वित्तीय समावेशन योजना का परिवर्धित रूप है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 अगस्त 2014 को वित्तीय समावेशन वाली इस महत्वाकांक्षी योजना की शुरुआत की, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में लोग आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा के अलावा नकद प्रबंधन को लेकर चिंतित रहते हैं। कभी-कभार ग्रामीणों के घर में चोरी भी हो जाती है या उनके परिवार के पुरुष सदस्य शराब या जुआ में पैसे उड़ा देते हैं। पशु, खाद व बीज खरीदने के लिए किसान को अक्सर गाँव के पास के बाजार या दूसरे शहर जाना पड़ता है। यात्रा के दौरान पैसों के गुम होने का खतरा बना रहता है। इसलिये, सरकार इस योजना की मदद से ग्रामीणों को आर्थिक एवं सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना चाहती है, क्योंकि बैंक में खाता खुलने से ग्रामीण अपनी जमा-पूँजी बैंक में रखेंगे, जिससे उनके पैसे चोरी या बर्बाद होने से बच जायेंगे। बैंक में खाता होने से उन्हें ऋण मिलने में भी आसानी होगी। बैंक से नहीं जुड़े होने के कारण ग्रामीण अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए या तो सूदखोर, साहूकार आदि की शरण लेता है या फिर किसी चिट-फंड कंपनी की। प्रधानमंत्री जनधन

योजना के तहत 16 जून 2021 तक 42 करोड़ 50 लाख खाते खोले जा चुके थे और इनमें 1.44 लाख करोड़ रूपये जमा थे. इन खोले गए खातों में 31 करोड़ रुपे कार्ड भी जारी किये गए हैं, जिससे डिजिटल लेनदेन में तेजी आ रही है. आज वित्तीय संस्थानों से जुड़ने के कारण ही किसानों या गरीबों के खाते में सीधे सहायता राशि अंतरित की जा रही है और सिर्फ इसी वजह से कोरोना काल में लाखों गरीबों को भूखे मरने से बचाने में सरकार सफल रही.

प्रधानमंत्री जनधन योजना के माध्यम से सरकार वित्तीय समावेशन की संकल्पना को पूरा करने के साथ-साथ सामाजिक सरोकारों को भी पूरा करना चाहती है। इसके अंतर्गत वित्तीय सेवाओं मसलन, बचत खाता खोलने से लेकर, धन अंतरण, ऋण (ओवरड्राफ्ट सीमा), बीमा आदि सुविधायें ग्राहकों को उपलब्ध कराई जा रही है। इस योजना की मदद से पहाड़ी इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को भी बैंक से जोड़ा जा रहा है।

बैंक शाखा, बिजनेस कोरेस्पोंडेंट (बीसी) या मिनी बैंक की उपलब्धता 5 किलोमीटर के दायरे में कितनी है, का पता करने के लिए सरकार ने एक भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित एप विकसित किया है, जिसका नाम जन धन दर्शक ऐप या जेडीडी एप है, जिसे राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) ने विकसित किया है. बैंक इस एप में लॉग-इन करके अपनी शाखाओं, बीसी और एटीएम से संबंधित जानकारी को भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) में अपलोड कर सकते हैं. जेडीडी एप में संग्रहित सूचना के अनुसार देशभर में बैंकों की 1.66 लाख शाखाएं, 4.35 लाख बीसी और 2.07 लाख एटीएम कार्यरत हैं. इस एप में 5.53 लाख गांवों की जानकारियां भी संग्रहित हैं, जिसके मुताबिक 5.52 लाख गांवों में 5 किलोमीटर की दूरी के भीतर बैंक शाखा या बीसी हैं।

इन आंकड़ों से पता चलता है कि देश में अभी भी शत-प्रतिशत वित्तीय समावेशन की संकल्पना साकार नहीं हो सकी है. वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 6,49,481 गाँव थे, लेकिन इनमें से 5,93,615 गाँवों में ही आबादी थी. अगर वर्ष 2011 की जनगणना को आधार मानें तो 93 प्रतिशत गाँववासियों की बैंकों तक पहुँच है. हालाँकि, 5 किलोमीटर की दूरी कोई कम दूरी नहीं है. गाँवों में सड़क नहीं होने के कारण गाँववासियों को छोटी दूरी तय करने में भी काफी ज्यादा समय लग जाता है.

कोरोना महामारी के दौरान प्रधानमंत्री जनधन योजना को अमलीजामा पहनाने के कारण ही किसान, गरीब और समाज के वंचित तबकों के खातों में सहायता राशि तुरंत पहुंचाई जा सकी। प्रधानमंत्री जनधन योजना के कारण ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों को रुपे कार्ड, मोबाइल बैंकिंग की

सुविधा, दुर्घटना व जीवन बीमा कवर, पेंशन आदि की सुविधायेँ मिल रही हैं। साथ ही, बैंकों में खाता खुलने से किसान, किसान क्रेडिट कार्ड, दूसरे प्रकार के ऋण, सब्सिडी आदि लाभ ले रहे हैं, जिससे उन्हें घर का अर्थ प्रबंधन करने में आसानी हो रही है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना के तर्ज पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई 2015 को कोलकाता में तीन बडी सामाजिक योजनाओं जैसे, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना को शुरू करने की घोषणा की। इनमें से दो बीमा से जुड़ी योजनाएं हैं, जबकि एक पेंशन से संबंधित। इन योजनाओं को शुरू गरीबों का सशक्तीकरण करने के लिए किया गया है, इन सामाजिक योजनाओं को लागू कराने की जिम्मेवारी बैंकों एवं बीमा कंपनियों की है।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के तहत किसी भी वजह से मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को दो लाख रूपये देने का प्रावधान है। बीमा अवधि 1 जून से 31 मई तक का होगा। योजना को जीवित रखने के लिए प्रत्येक साल 31 मई तक बीमा का नवीनीकरण कराना होगा। योजना का लाभ 18 से 50 साल आयु वर्ग के बचत बैंक खाताधारक उठा सकते हैं. एक बार बीमा करा लेने के बाद बीमित व्यक्ति 55 साल की उम्र तक बीमा का लाभ ले सकेगा। इस योजना की प्रीमियम 330 रुपये है, जो हर साल 31 मई तक बीमा के नवीनीकरण के लिए देनी होगी। 330 रुपये के प्रीमियम में 289 रुपये बीमा कंपनी के खाते में, 30 रुपये एजेंट को, और 11 रुपये बैंक को प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में दिये जायेंगे। बीमा का प्रीमियम बैंक प्रणाली द्वारा स्वचालित तरीके से नामे की जायेगी। अगर कोई योजना का सदस्य देरी से बनता है तो नये सदस्यों को भी प्रीमियम की पूरी राशि देनी होगी। इस योजना की मास्टर पॉलिसी गृह बैंक या जिस बैंक में बीमित व्यक्ति का बचत खाता है में उपलब्ध होगा। 55 साल की उम्र पूरी होने या बैंक खाता बंद होने या फिर खाते में अपर्याप्त राशि होने पर बीमा कवर समाप्त हो जायेगा। एक से अधिक बैंक खातों के जरिये एक से अधिक बीमा कराने पर बीमित व्यक्ति को एक ही बीमा का लाभ मिलेगा और एक से अधिक बार जमा की गई प्रीमियम की राशि को नहीं लौटाया जायेगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना के कारण मृत्यु होने पर बीमित व्यक्ति को दो लाख रूपये मिलेंगे और दुर्घटना में दोनों आँखों की रोशनी जाने, दोनों हाथों या दोनों पैरों के अपंग होने, एक आँख की रोशनी जाने और एक हाथ या पैर के अपंग होने पर बीमित व्यक्ति को दो लाख रूपये मिलेंगे। एक आँख की रोशनी जाने या एक हाथ या पैर के अपंग होने पर बीमित व्यक्ति को

एक लाख रूपये मिलेंगे। बीमा की अवधि 1 जून से 31 मई रखी गई है, जिसका हर वर्ष नवीनीकरण कराना होगा, अन्यथा प्रीमियम के भुगतान नहीं होने पर बीमा का लाभ बीमित व्यक्ति को नहीं मिलेगा। इस योजना का लाभ 18 से 70 साल के आयु वर्ग के हर बचत बैंक खाताधारक, जिसका केवाईसी हो चुका है, उठा सकता है। इस बीमा कवर को प्राप्त करने के लिए हर साल 12 रुपये का प्रीमियम देना होगा। 12 रुपये के प्रीमियम में 10 रुपये बीमा कंपनी को, एक रुपया एजेंट को एवं शेष एक रुपया बैंक को प्रशासनिक खर्च की प्रतिपूर्ति के रूप में मिलेगा। इस योजना का लाभ उठाने के लिए हर साल 31 मई तक बैंक में आवेदन दिया जा सकता है। प्रीमियम की राशि स्वचालित तरीके से खाते से डेबिट की जायेगी। विलंब से योजना का भागीदार बनने वालों को भी प्रीमियम की पूरी राशि अदा करनी होगी। खाताधारक के गृह बैंक में बीमा की मास्टर पॉलीसी उपलब्ध होगी। 70 साल की उम्र होने या बैंक खाता बंद होने या इसमें अपर्याप्त राशि होने पर बीमित व्यक्ति का बीमा कवर समाप्त हो जायेगा। एक से अधिक बैंक खातों के जरिये एक से अधिक जगह बीमा करवाने वालों की एक ही बीमा कवर वैध होगी और एक से अधिक बार जमा प्रीमियम राशि को लौटाया नहीं जायेगा।

अटल पेंशन योजना

इस योजना में एक, दो, तीन, चार और पाँच हजार रुपये मासिक पेंशन प्राप्त करने का विकल्प उपलब्ध है। 18 से 40 साल की उम्र के ऐसे बैंक खाताधारक जिनकी आय कर योग्य नहीं है और वे किसी अन्य संवैधानिक सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ नहीं उठा रहे हैं इस योजना के पात्र होंगे। 60 साल की उम्र पूरी होने के बाद पेंशन का विकल्प चुनने वाले खाताधारक को पेंशन देने का प्रावधान योजना में किया गया है।

निष्कर्ष:-

भारत एक लोकतान्त्रिक एवं कल्याणकारी देश है। इसलिए, गरीबों को बुनियादी सुविधा मुहैया कराने एवं उनके जीवनयापन के लिये आवश्यक तंत्रों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने की ज़िम्मेदारी सरकार की है। सरकार उन्हें भगवान भरोसे नहीं छोड़ सकती है। इसलिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी एक तरफ प्रधानमंत्री जनधन योजना की मदद से वित्तीय समावेशन के लक्ष्य को हासिल करने, डिजिटल इंडिया की संकल्पना को मूर्त रूप देने, आमजन को आत्मनिर्भर बनाने आदि का काम कर रहे हैं तो दूसरी तरफ आम आदमी के जीवन को आर्थिक रूप से सुरक्षित बनाने के लिए बीमा और पेशन योजनाओं को चलाने का काम कर रहे हैं.

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के कॉरपोरेट केंद्र मुंबई के आर्थिक अनुसंधान विभाग में कार्यरत हैं। आर्थिक मामलों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

श्री नरेन्द्र मोदी ने भारत में गरीबी समाप्त करने के उद्देश्य से विदेशी निवेश को भारत की ओर मोड़ने में सफलता पाई है

प्रहलाद सबनानी

21 वीं सदी के तीसरे दशक में समाहित, वर्ष 2022 में भारत अपनी स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण करेगा। आज देश के अंदर ही नहीं बल्कि देश के बाहर भी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लगातार कई वर्गों, अर्थशास्त्रियों, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों में यह धारणा प्रबल होती जा रही है कि न केवल अगला दशक बल्कि अगली सदी भी भारत के प्रभुत्ववाली होने की प्रबल सम्भावना बनती जा रही है। इसकी नींव पिछले 7 वर्षों के दौरान माननीय श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लिए गए कई निर्णयों के चलते रखी जा चुकी है।

भारत इस समय विश्व के सबसे मजबूत देशों में से एक बन गया है। आज भारत की आवाज पूरे विश्व में गम्भीरता से सुनी जा रही है। कोई भी देश भारत को आज हल्के में नहीं लेता है। राजनैतिक तौर पर भारत की ताकत विश्व में बढ़ी है। वैश्विक स्तर पर सभी बड़ी ताकतें अमेरिका, रूस, जापान, आस्ट्रेलिया, फ्रान्स, ब्रिटेन आदि देश भारत के पक्ष में खड़े दिखाई देते हैं। वे आज भारत को गम्भीरता से लेते हैं। यह सब एकाएक नहीं हुआ है बल्कि इस सबके पीछे छिपी है भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की देश के प्रति अगाध श्रद्धा, प्रेम, लग्न एवं दिनरात की लगातार मेहनत। वे जिस किसी देश अथवा अंतर राष्ट्रीय सम्मेलन में जाते हैं वहां भारत के आर्थिक विकास की बात करना नहीं भूलते हैं। अपने पक्ष को कुछ इस प्रकार रखते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति अपने स्वयं के लिए विदेशी निवेशकों से सहायता मांग रहा हो।

विदेशी निवेशकों को निमंत्रण

आप को याद होगा, दिनांक 25 सितम्बर 2019 को न्यूयॉर्क में ब्लूम्बर्ग वैश्विक व्यापार फोरम 2019 में श्री नरेन्द्र मोदी ने विदेशी निवेशकों को निमंत्रण देते हुए कहा था कि वे भारत में अपने निवेश को बढ़ाएं क्योंकि विकास ही आज भारत की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। आज भारत की जनता उस सरकार के साथ खड़ी है जो व्यवसाय का माहौल सुधार ने के लिए बड़े से बड़े और कढ़े से कढ़े फैसले लेने में पीछे नहीं रहती है।

आज भारत में एक ऐसी सरकार है जो व्यापार जगत का सम्मान करती है सम्पत्ति निर्माण का सम्मान करती है। आज भारत एक अद्वितीय स्थिति में आकर खड़ा हो गया है। देश में तेज गति से विकास हो रहा है, गरीबी में कमी आ रही है, लोगों की क्रय शक्ति बढ़ रही है जिससे विभिन्न वस्तुओं की मांग में वृद्धि दृष्टिगोचर है।

माननीय प्रधानमंत्री ने विदेशी निवेशकों का आह्वान करते हुए यह भी कहा था कि भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। देश में तेज गति से चालित परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए नए-नए राजमार्गों का निर्माण किया जा रहा है। बड़े-बड़े शहरों में मेट्रो रेल्वे का जाल बिछाया जा रहा है। बंदरगाहों एवं हवाई अड्डों को आधुनिक बनाया जा रहा है। इन सभी क्षेत्रों में भारी मात्रा में निवेश किया जा रहा है। भारत में बुनियादी ढांचे के विकास पर आज जितना निवेश भारत सरकार कर रही है उतना निवेश देश में पहिले कभी नहीं किया गया है। देश में आगे आने वाले कुछ वर्षों में 100 लाख करोड़ रुपए का खर्च आधुनिक बुनियादी ढांचे को खड़ा करने पर किया जाएगा।

भारत के सामाजिक बुनियादी ढांचे पर भी लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। भारत के विकास की कहानी में अब गुणात्मक एवं परिमाणात्मक दोनों ही स्थितियों में छलांग लगाने को तैयार है। अब भारत ने अपने विकास के लिए एक बड़ा लक्ष्य तय कर लिया है। वर्ष 2024-25 तक देश को 5 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने का। जब 2014 में वर्तमान सरकार सत्ता में आई थी, तो देश की अर्थव्यवस्था करीब-करीब 2 लाख करोड़ अमेरिकी डॉलर की थी। इस बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए देश के पास योग्यता भी है, साहस भी है और परिस्थितियां भी अनुकूल हैं।

यह था भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेन्द्र मोदी का वैश्विक समुदाय को सम्बोधन, ऐसा लग रहा है जैसे किस कम्पनी का मुख्य कार्यपालन अधिकारी अपनी बात रख रहा हो। यह सब देश के प्रति उनकी अगाध श्रद्धा एवं देश में गरीबी समाप्त करने की चिंता को झलकाता है।

विदेशी निवेशकों को दिए गए निमंत्रण का असर

भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी द्वारा विदेशी निवेशकों को दिए गए उक्तवर्णित निमंत्रण का असर बहुत ही प्रभावशाली रहा है। जिसके चलते, दिनांक 04 सितंबर 2021 को समाप्त सप्ताह के दौरान भारत ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि दर्ज की है। भारतीय इतिहास में पहली बार देश में विदेशी मुद्रा भंडारने 64,245 करोड़ अमेरिकी डॉलर के स्तर को छुआ है। भारत के इतिहास में विदेशी मुद्रा भंडार ने कभी भी इस स्तर को नहीं छुआ है।

वित्तीय समावेशन

केवल विदेशी व्यापार एवं विदेशी निवेश के क्षेत्र में ही नहीं बल्कि श्री नरेन्द्र मोदी के कार्यकाल में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में भी अकल्पनीय सुधार हुआ है।

भारत में वर्ष 1947 में 70 प्रतिशत लोग गरीबी की रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे थे। जब कि अब वर्ष 2020 में देश की कुल आबादी का लगभग 22 प्रतिशत हिस्सा गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन कर रहा है। जब कि 1947 में देश की आबादी 35 करोड़ थी जो आज बढ़कर 136 करोड़ हो गई है। देश में वित्तीय समावेशन को सफलतापूर्वक लागू किए जाने के कारण ही गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों की संख्या में भारी कमी देखने में आई है। केंद्र में वर्तमान मोदी सरकार के कार्यभार ग्रहण करने के बाद से तो वित्तीय समावेशन के कार्यान्वयन में बहुत अधिक सुधार देखने में आया है। उसके पीछे मुख्य कारण देश में विभिन्न वित्तीय योजनाओं को डिजिटल प्लेटफार्म पर ले जाना है। आज भारत के करीब-करीब प्रत्येक नागरिक के पास यूनिक आई डी है, मोबाइल फोन है, बैंक अकाउंट है, जिसके कारण लक्षयित सेवाओं को प्रदान करने में तेजी आई है। केंद्र सरकार द्वारा प्रारम्भ की गई जन-धन योजना ने इस संदर्भ में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है। जन-धन योजना के अंतर्गत कुल 42 करोड़ से अधिक देशवासियों के खाते विभिन्न बैंकों में खोले गए हैं, जिनके खातों में आज सीधे ही सब्सिडी का पैसा केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा हस्तांतरित किया जा रहा है। मनरेगा योजना की बात हो अथवा केंद्र सरकार की अन्य योजनाओं की बात हो, पहले ऐसा कहा जाता था कि केंद्र से चले 100 रुपए में से शायद केवल 8 रुपए से 16 रुपए तक ही अंतिम हितग्राही तक पहुंच पाते हैं, परंत आज हितग्राहियों के खातों में सीधे ही राशि के जमा करने के कारण बिचोलियों की भूमिका एकदम समाप्त हो गहै एवं हितग्राहियों को पूरा का पूरा 100 प्रतिशत पैसा उनके खातों में सीधे ही जमा हो रहा है। यह वित्तीय समावेश न की दृष्टि से एक क्रांतिकारी कदम सिद्ध हुआ है।

गरीब तबके हेतु विशेष योजनाएं

वर्ष 2014 में, केंद्र में माननीय श्री नरेन्द्र मोदी की सरकार के सत्ता में आने के बाद से ही गरीब तबके के लोगों में प्रसन्नता की भावना विकसित करने के उद्देश्य से कई योजना ओं का सफलता पूर्व क किर्यान्वयन किया गया है। इन में मुख्य रूप से शामिल हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना – जिसके अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक आवासों का निर्माण किया जा चुका है। सौभाग्य योजना – जिसके अंतर्गत 100 प्रतिशत गांवों में बिजली उपलब्ध करवा दी गई है। स्वच्छ भारत अभियान – जिसके अंतर्गत 10 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है। उज्जवला योजना – जिसके अंतर्गत 9 करोड़ से अधिक एलपीजी के कनेक्शन दिलवाए गए हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और शहरी गैसवितरण नेटवर्क के जरिये रसोई घरों तक पाइपसे सीधे गैस पहुंचाने जैसे कदमों से भारत में 28 करोड़ से अधिक परिवार इसके दायरे में आग ये हैं। वर्ष 2024 तक ग्रामीण इलाकों के हर घर में जल पंहुचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए अलगसे "जल

शक्ति मंत्रालय" बनाया गया है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत देश के 97 प्रतिशत गांवों को समस्त मौसम में उपलब्ध सड़कों के साथ जोड़ दिया गया है। अब इन सड़कों को अप ग्रेड किया जा रहा है । प्रधान मंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान भी चलाया जा रहा है, इस अभियान के अंतर्गत 2 करोड़ से अधिक ग्रामीणों को डिजिट लक्षेत्र में प्रशिक्षित किया जा चुका है। इससे ग्रामीणों की उत्पादकता में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज हो रही है। प्रधानमंत्री वाणी योजना को भी पूरे देश में लागू किया जा रहा है जिसके अंतर्गत वाइफाई हाटस्पाट्स की स्थापना की जा रही है ताकि देश में इंटरनेट का जाल बिछाया जा सके। इससे ग्रामीण इलाकों में भी ई-कामर्स सुविधाएं व वाइफाई हाटस्पाट्स बढ़ेंगे तथा ग्रामीण इलाकों में भी कार्यक्षमता के स्तर में सुधार होगा। ग्रामीण इलाकों में भी लोग अपना व्यवसाय शुरू कर सकेंगे। आज के जमाने में युवा वर्ग को तकनीक के साथ जोड़ना जरूरी हो गया है।

भारत की आत्मनिर्भरता में पूरे विश्व को लाभ

देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी ने "अमेरिका-भारत स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम के तीसरे लीडरशिप समिट", को सम्बोधित करते हुए कहा है कि 130 करोड़ भारतीय अब देश को आत्मनिर्भर बनाने के मिशन पर निकल पड़े हैं। भारत के आत्म निर्भर बनने की परिभाषा में पूरे विश्व का कल्याण निहित है। भारत ने यह बार बार दोहराया भी है कि हमारा अंतिम उद्देश्य पूरे विश्व में बंधुत्व की भावना का संचार करना एवं समस्त प्राणियों के सुखी होने से है। इसीलिए भारत अब लोकल (स्थानीय) को ग्लोबल (वैश्विक) रूप देना चाहता है।

पूरे विश्व का भारत पर विश्वास

अब तो विश्व के अधिकतर देशों को प्रबल विश्वास होता जा रहा है कि भारत आने वाले समय में पूरे विश्व में सबसे अधिक विदेशी निवेश आकर्षित करने वाला स्थल बनने जा रहा है। क्योंकि, यहां पिछले 70 वर्षों से लगातार लोकतंत्र बहाल रहा है, राजनैतिक स्थिरता का माहौल है, ईज आफ डूइंग बिजिनेस में लम्बी छलांग लगाई है, आर्थिक क्षेत्र में हाल ही में कई सुधार कार्यक्रम लागू किए गए हैं, पॉलिसी में स्थिरता है। साथ ही, वर्तमान में केंद्र सरकार ने कोरोना महामारी की विकराल समस्या का जिस समझ बूझ से मुकाबला किया है उसके कारण मौतों की संख्या अन्य देशों की तुलना में काफी कम रही है। कोरोना की जांच के लिए केवल एक टेस्टिंग लेबोरेटरी से शुरुआत कर अल्प समय में ही देश में हजारों की संख्या में टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई हैं। कोरोना महामारी के दौरान देश के करीब 80 करोड़ लोगों के लिए मुफ्त अनाज एवं आर्थिक सहायता की व्यवस्था सफलतापूर्वक की गई। अल्प समय में ही 75 करोड़ से अधिक कोरोना टीकाकरण के डोज नागरिकों को लगा दिए गए हैं। अतः भारत की साख एक जिम्मेदार एवं योग्य देश के रूप में पूरे विश्व में स्थापित हुई है।

(लेखक बैंकिंग क्षेत्र से सेवानिवृत्त हैं। आर्थिक विषयों के जानकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

नरेन्द्र मोदी: असाधारण, कुशल एवं प्रभावी वक्ता

लोकेन्द्र सिंह

सार्वजनिक जीवन में संवाद कला का बहुत महत्व है। व्यक्तिगत स्तर और छोटे समूह में लोगों को आकर्षित करना एवं उन्हें अपने से सहमत करना अपेक्षाकृत आसान होता है। किंतु, जन (मास) को अपने विचारों से सहमत करना और अपने प्रति उसका विश्वास अर्जित करना कठिन बात है। सार्वजनिक जीवन में काम करने वाले लोग किसी न किसी माध्यम से ही जन सामान्य तक अपनी पहुँच बनाते हैं। इस प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण है, व्यक्ति किस प्रकार अपने विचार प्रस्तुत करता है। आवश्यक है कि वह जिस रूप में सोच रहा है, वह उसी रूप में जनता के बीच पहुँचे। जो लोग इस प्रकार संवाद कला को साध लेते हैं, वह जनसामान्य से जुड़ जाते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसी संवाद कला को सिद्ध कर लिया है। वह असाधारण वक्ता और प्रभावी संचारक हैं। प्रधानमंत्री मोदी संचार के 7-सी के सिद्धांत को जीते हैं। संचार के विशेषज्ञ फ्रांसिस बेटजिन ने बताया है कि 7-सी के सिद्धांत का उपयोग कर संचारक बहुत ही सरलता और प्रभावी ढंग से जन (मास) के मस्तिष्क में अपनी बात (संदेश) को पहुंचा सकता है। बहुत बड़े जनसमुदाय से अपनत्व स्थापित कर सकता है। इस सिद्धांत की सातों सी- स्पष्टता (Clarity), संदर्भ (Context), निरंतरता (Continuty), विश्वसनीयता (Credibility), विषय वस्तु (Content), माध्यम (Channel) और पूर्णता (Completeness) प्रधानमंत्री मोदी के भाषण में झलकती हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो संदेश देना चाहते हैं, समाज तक वह संदेश स्पष्ट रूप से पहुँचता है। वह अपनी बात को संदर्भ के साथ प्रस्तुत करते हैं, इससे लोगों को उनका संदेश समझने में आसानी होती है और उसमें रुचि भी जाग्रत होती है। वह अपनी बात को निरंतरता और पूर्णता के साथ कहते हैं। किस तरह की बात करने के लिए कौन-सा माध्यम उपयुक्त है, यह भी वह भली प्रकार जानते हैं। युवाओं के साथ संवाद करना है तो वह नवीनतम तकनीक का उपयोग करते हैं। सोशल मीडिया के सभी मंच और नमो एप के माध्यम से वह तकनीक के साथ जीने वाली नयी पीढ़ी से संवाद करते हैं तो इस पीढ़ी को मोदी अपने निकट नजर आते हैं। सुदूर क्षेत्रों में संवाद करना है तो वह रेडियो को चुनते हैं। अहिंदी क्षेत्रों में क्षेत्रीय भाषा में अपने भाषण की शुरुआत कर, वहाँ उपस्थित

जनता का अभिवादन कर वह उनका दिल जीत लेते हैं। यही कारण है कि उनको चाहने वाले लोग गुजराती और उत्तर भारत में ही नहीं, वरन भारत के दूसरे क्षेत्रों में भी समानुपात में हैं। कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी किसी कुशल संचारक की तरह प्रभावी संचार के सभी तत्वों को ध्यान में रखकर जन संवाद करते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा को नजदीक से देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि आज वह जिस शिखर पर हैं, वहाँ पहुँचने में उनकी संवाद शैली की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राजनीति को लंबे समय बाद ऐसा राजनेता मिला है, जिसके संबोधन की प्रतीक्षा समूचे देश को रहती है। लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले भाषण अब औपचारिक नहीं रह गए। वह एक विशेष वर्ग तक भी सीमित नहीं रह गए हैं। अब देश का जनसामान्य उनको सुनता है। जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी बोलते हैं तो देश ही नहीं अपितु दुनिया के कान उनके वक्तव्य पर टिके होते हैं। मोदी को चाहने वाले ही नहीं, अपितु उनकी आलोचना करने वाले लोग भी उन्हें अत्यंत ही ध्यानपूर्व सुनते हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की संवाद शैली का असर है कि रेडियो फिर से जनमाध्यम बन गया। प्रधानमंत्री मोदी के 'मन की बात' को सुनने के लिए गाँव-शहर में चौपाल लगती है। वह जब विदेश में जाते हैं तो प्रवासी भारतीय उनको सुनने के लिए आतुर हो जाते हैं। विदेशों में भारतीय राजनेता को सुनने के लिए इतनी भीड़ कभी नहीं देखी गई है। दरअसल, उन्हें यह अच्छे से ज्ञात है कि कब, कहाँ और किसके बीच अपनी बात को कैसे कहना है? यदि हम यह मान भी लें कि राजनीतिक सभाओं में भीड़ जुटाना एक प्रकार का प्रबंधन है। फिर भी अब वह दौर नहीं रहा जब आम आदमी हेलीकॉप्टर देखने के आकर्षण में सभा स्थल तक पहुँच जाता था। उस समय अपने प्रिय नेता को देखने के लिए संचार के अत्यधिक माध्यम भी नहीं थे। जबकि आज तो हर समय राजनेता की छवि हमारे सामने उपस्थित रहती है। दूसरी बात यह कि सभा स्थल की अपेक्षा घर में बैठ कर अधिक आराम और अच्छे से अपने प्रिय नेता को टेलीविजन पर सीधे प्रसारण में सुना-देखा जा सकता है। ऐसे समय में भी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को प्रत्यक्ष सुनने के लिए जनता जुटती है तो यह अपने आप में आश्चर्य और शोध-अध्ययन का विषय बनता है। यह उनकी असाधारण भाषण कला का जादू है जो लोग खिंचे चले आते हैं। वे अपनी इस कला से श्रोताओं को मंत्रमुग्ध करना जानते हैं।

वह जानते हैं कि आज के युवाओं को किस तरह की भाषा सुनना पसंद है। हिन्दी प्रेमी होने के बाद भी वह अपने भाषण में कुछ वाक्य/तुकबंदी अंग्रेजी के शब्दों की करते हैं। वह तुकबंदी तेजी से लोगों की जुबान पर चढ़ जाती है, जैसा कि वह चाहते थे। जैसे- रिकॉर्ड देखिए, टेप रिकॉर्ड नहीं, मिनिमम गवर्नमेंट- मैक्सिमम गवर्नेंस, रिफोर्म-परफोर्म-ट्रांसफोर्म, नेशन

फर्स्ट (राष्ट्र सबसे पहले)। GST को उन्होंने कुछ इस तरह परिभाषित किया- ग्रोइंग स्ट्रॉन्गर टुगेदर। वहीं, अंग्रेजी के अल्फाबेट ABCD को उन्होंने आदर्श, बोफोर्स, कोयला और दामाद घोटाले से जोड़कर आकर्षक अंदाज में अपना संदेश जनता के बीच पहुँचाया। BHIM- इस एप को उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर से जोड़ दिया। उनका दिया नारा 'सबका साथ-सबका विकास' और 'अच्छे दिन आएंगे' आज भी चर्चा और बहस के केंद्र में रहते हैं। अपने राजनीतिक विरोधियों पर जोरदार और असरदार हमला बोलने के लिए वह कैसे 'आकर्षक शब्द' गढ़ते हैं, उसका एक उदाहरण स्कैम भी है। उत्तर प्रदेश के चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने मेरठ की एक रैली में स्कैम (Scam) का नया अर्थ बताया था। उन्होनें S से समाजवादी, C से कांग्रेस, A से अखिलेश और M से मायावती को बताया था। इस तरह के प्रयोगों से प्रधानमंत्री मोदी अपने संदेश को प्रभावी और स्थायी तौर पर लोगों के बीच पहुँचाने में सफल होते हैं। इससे भाषण में एक प्रकार की रुचि भी जागती है। इसलिए ही उनका भाषण लोगों के दिमाग में उतर जाता है और जनसामान्य में चर्चा का विषय बनता है।

वाकपटुता में उनका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। अपने विरोधियों के आरोपों और अमर्यादित शब्दों को भी वह अपने हित में उपयोग कर लेते हैं। वह स्वयं स्वीकारते हैं कि विरोधियों के फेंके पत्थर (अपशब्दों) से उन्होंने अपने लिए पहाड़ बना लिया है। प्रियंका गांधी ने जब आम चुनाव 2014 से पूर्व अपने एक भाषण में 'नीच राजनीति' शब्द का प्रयोग किया तो नरेन्द्र मोदी ने अपनी वाकपटुता और संवाद कुशलता से उस शब्द को पकड़ कर कांग्रेस को सीधे चोट पहुँचाई। गुजरात चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने भी उनके लिए सीधे-सीधे 'नीच' शब्द का उपयोग किया, जिसकी क्षतिपूर्ति कांग्रेस ने गुजरात चुनाव में अपनी पराजय से की। उत्तरप्रदेश चुनाव के दौरान अखिलेश यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के गधा बताया था। जिस पर प्रधानमंत्री मोदी ने जवाबी वार करते हुए कहा कि मैं गर्व से गधे से प्रेरणा लेता हूं और देश के लिए गधे की तरह काम करता हूं। सवा सौ करोड़ देशवासी मेरे मालिक हैं। गधा वफादार होता है उसे जो काम दिया जाता है वह पूरा करता है। यह गधा शब्द कांग्रेस को भारी पड़ गया। कहने का अभिप्राय इतना है कि प्रधानमंत्री संवाद कला में इस स्तर तक निपुण हैं कि वह अपने लिए कहे गए अपशब्दों को भी अपनी ताकत बना लेते हैं।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के भाषण देश की जनता के बीच विश्वास का एक वातावरण बनाते हैं। वह आह्वान करते हैं और देश की जनता उनका अनुसरण करने निकल पड़ती है। प्रधानमंत्री मोदी की वाणी का जादू है कि देश के निश्छल नागरिकों के अंतर्मन में स्वच्छता के प्रति आंदोलन का भाव प्रकट हो जाता है। छोटे

बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक स्वच्छाग्रही बन जाते हैं। मोदी के कहने पर लाखों लोग गैस की सबसिडी छोड़ देते हैं। देशवासी उनके कहने पर अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को किसी बड़े धार्मिक-राष्ट्रीय उत्सव की तरह मनाते हैं। यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की वाणी के प्रति जनता का भरोसा था कि अनेक प्रकार के कष्ट सहकर भी लोगों ने नोटबंदी के बाद पूरी तरह अनुशासन का पालन किया, जबकि समूचा विपक्ष और कुछ मीडिया संस्थान जनता को विद्रोह के लिए लगातार भड़का रहे थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को देश की जनता क्रिकेट के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर की तरह देखती है। भारतीय दल कठिन स्थिति में फंसा है, किंतु यदि पिच पर सचिन खड़े हैं तो देश की जनता को एक उम्मीद रहती है कि मुकाबले का परिणाम देश के पक्ष में आएगा। इसी तरह का विश्वास देश की जनता को नरेन्द्र मोदी पर है। जब मोदी बल्लेबाजी (अपना पक्ष रखने) के लिए राजनीति की पिच पर उतरते हैं तो समूचा देश नि:शब्द उन्हें ध्यानपूर्वक सुनता है। अभी हाल में अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दौरान सरकार की ओर से पक्ष रखते समय उन्होंने काफी लंबा भाषण दिया, किंतु उनके उस भाषण को पूरे देश ने चाव के साथ सुना। उनके भाषण को देश सुनता है, इसका प्रमाण अनेक टेलीविजन चैनक के टीआरपी के आंकडे हैं। इस समय देश में वह इकलौते नेता हैं, जिनके भाषणों का ज्यादातर समाचार चैनल सीधा प्रसारण करते हैं, चाहे वह भाषण देश के किसी हिस्से से दिया जा रहा हो या फिर विदेशी जमीन से। बहरहाल, भारतीय राजनीति में इतने अच्छे वक्ता राजनेता कम ही हैं। वर्तमान समय में तो प्रधानमंत्री मोदी के मुकाबले का कुशल संचारक अन्य कोई दिखाई नहीं देता है। पिछले सात-आठ वर्ष से नरेन्द्र मोदी लगातार बोल रहे हैं, इसके बाद भी उनको सुनने की भूख देश की जनता में बची हुई है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की यात्रा को नजदीक से देखते हैं तो हमें ध्यान आता है कि आज वह जिस शिखर पर हैं, वहाँ पहुँचने में उनकी संवाद शैली की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। भारतीय राजनीति को लंबे समय बाद ऐसा राजनेता मिला है, जिसके संबोधन की प्रतीक्षा समूचे देश को रहती है। लाल किले की प्राचीर से दिए जाने वाले भाषण अब औपचारिक नहीं रह गए। वह एक विशेष वर्ग तक भी सीमित नहीं रह गए हैं। अब देश का जनसामान्य उनको सुनता है।

(लेखक सहायक प्राध्यापक एवं जनसंपर्क अधिकारी, माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय, भोपाल में हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं)

धारा-370 हटने से देश की अखंडता हुई अक्षुण्ण

प्रमोद भार्गव

आजादी के बाद भी कुछ अनुत्तरित प्रश्न 70 साल बने रहे। इन प्रश्नों में धारा-370, राम मंदिर, तीन तलाक और सामान्य नागिरक संहिता ऐसे प्रश्न हैं, जो प्रत्येक सच्चे भारतीय के मन को बेचैन करते रहे हैं। इनमें सबसे अहम् प्रश्न जम्मू-कश्मीर में अस्थाई रूप से लागू की गई धारा-370 और 35-ए थीं। इस अस्थाई अनुच्छेद को हटाया जा सकता था, किंतु टाला जाता रहा। इसे हटाया जाना तब अत्यंत अनिवार्य हो गया था, जब रातोंरात आतंकियों की बंदूकों की नोक पर पांच लाख पंडित, सिख, बौद्ध, जैन और कुछ दलितों को ऋषि-कश्यप की पवित्र धरती से खदेड़ दिया गया था। इस समय केंद्रीय सत्ता की कमान प्रधानमंत्री के रूप में वीपी सिंह के हाथों थी और गृहमंत्री मुफ्ती मोहम्मद सईद थे। अब यह समझ से परे है कि प्रधान और गृहमंत्री की यह जोड़ी तत्कालीन राज्यपाल जगमोहन सिंह द्वारा सेना की मांग के बावजूद सेना भेजने से क्यों कतरा गई ? यह प्रश्न आज भी अनुत्तरित है। वीपी सिंह ने देश की अखंडता के साथ यह खिलवाड़ सिर्फ इसलिए किया, जिससे सईद की जो पार्टी वीपी सिंह के लिए वैशाखी का काम कर रही थी, वह समर्थन वापस न ले ले। कुर्सी बचाने के लिए देश की संप्रभुता से यह खिलवाड़ एक राष्ट्रघाती पहल थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह ने 5 और 6 अगस्त 2019 को कुर्सी की परवाह किए बिना लोकतांत्रिक तरीके से संवैधानिक प्रक्रिया पूरी कर अलगाव की दोनों धाराओं को खत्म कर दिया और देश की अखंडता को सुरक्षित करने के साथ आजादी के बाद सबसे अहम् अनुत्तरित प्रश्न का हल भी कर दिया।

इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर में निरंतर हालात बद रहे हैं। पत्थरबाजी खत्म हो गई तीन दशकों से बंद पड़े अनेक मंदिरों के द्वार खुल गए हैं। 15 अगस्त स्वाधीना दिवस को जगह-जगह राष्ट्रगान हुआ और जनमाष्ठमी को भगवान कृष्ण का श्रीनगर की सड़कों पर कीर्तन-भजन गाते हुए जुलूस निकला। समरसता के ये उपाय कालांतर में और मजबूत होंगे। आश्चर्य नहीं कि एक दिन वह भी देखने में आए कि जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी 370 के विरोध में कश्मीर की धरती पर शहीद हुए थे, उनकी आदमकद प्रतिमा श्रीनगर के किसी चैक

पर अस्तित्व में आ जाए ? हालांकि सुखद संकेत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिल्ली में बुलाई बैठक से ही मिलने लग गए हैं। क्योंकि बैठक अत्यंत सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न हुई थी। यह सौहार्दता कश्मीर का भविष्य उज्जवल करने का मार्ग प्रशस्त कर रही है। प्रधानमंत्री और गृहमंत्री अमित शाह ने इस बहुदलीय बैठक में भरोसा जताया था कि जम्मू-कश्मीर में परिसीमन के बाद विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे और हालात सामान्य होने पर पूर्ण राज्य का दर्जा भी दे दिया जाएगा। साफ है, चुनाव के बाद सरकार किसी की भी बने घाटी का बहुलतावादी चरित्र उभरेगा और सर्वांगीण विकास का सिलसिला शुरू हो जाएगा। यही वे उपाय हैं, जिनसे जम्मू-कश्मीर के युवाओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं पूरी होंगी। क्योंकि अभी तक दो दलों के परिवार की इस राज्य की सत्ता का सुख भोग रहे थे। जिला विकास परिषद् के चुनाव से भी राजनीतिक प्रक्रिया बहाल हुई और अनेक युवाओं को नेतृत्व का अवसर मिल गया।

हालांकि कुछ अलगाववादी अभी भी अनुच्छेद-370 की बहाली की उम्मीद लगाए बैठे हैं। किंतु इसकी वापसी अब दूर की कौड़ी है। वैसे भी 370 का मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है, इसलिए उसकी बहाली का कोई नतीजा निकलने वाला नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद हटाने की प्रक्रिया संसद के दोनों सदनों से पूरी हुई है। इसकी वापसी इसलिए भी संभव नहीं है, क्योंकि यह एक अस्थाई अनुच्छेद था और बीते दशकों में इसके अनेक प्रावधान खत्म भी कर दिए गए हैं। जवाहरलाल नेहरू भी इसके पक्ष में नहीं थे, इसलिए उन्होंने कहा भी था, कि यह घिसते-घिसते स्वयं घिस जाएगा। सरदार पटेल और संविधान निर्माता डॉ अंबेडकर भी इसके पक्ष में नहीं थे। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भी इसे हटाने की कोशिश की थी। लिहाजा इसको हटाने की बात करने वाले नेता दिन में स्वप्न देख रहे हैं। अनुच्छेद बहाली के वनिस्वत जम्मू-कश्मीर के प्रत्येक दल की जुम्मेबारी बनती है कि वे अब कश्मीर की धरती पर विस्थापिकों की वापसी की पहल करें और उनका सम्मानजनक पुर्नवास कराएं ? याद रहे 1979-90 में घाटी में आतंक का उफान आया और दो-तीन दिन के भीतर ही करीब पांच लाख गैर-मुस्लिम खदेड़ दिए गए थे, जो आज भी दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। इस कठिन परिस्थिति में फारूख अब्दुल्ला संकट से मुंह मोड़कर लंदन प्रवास पर चले गए थे। अतएव जब तक इन विस्थापितों का पुर्नवास नहीं होगा, तब तक न तो कश्मीर में बहुलतावादी चरित्र सामने आएगा और न ही अनुच्छेद-370 खत्म होने का कोई अर्थ रह जाएगा?

जम्मू-कश्मीर के विभाजन और विधानसभा सीटों के विभाजन संबंधी पुनर्गठन विधेयक-2019, 31 अक्टूबर 2019 को लागू कर दिया गया था।

इसके लागू होने के बाद इस राज्य राज्य की भूमि का ही नहीं राजनीति का भी भूगोल बदलेगा। नए सिरे से परिसीमन व आबादी के अनुपात में जम्मू-कश्मीर की नई विधानसभा का जो आकार सामने आएगा, उसमें सीटें घट अथवा बढ़ सकती हैं। बंटवारे के बाद जम्मू-कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित राज्य हो गए हैं। दोनों जगह दिल्ली व चंडीगढ़ की तरह की तरह मजबूत उप राज्यपाल सत्ता-शक्ति के प्रमुख केंद्र के रूप में अस्तित्व में आ गए हैं। लद्दाख में विधानसभा नहीं होगी। परिसीमन के लिए आयोग का गठन किया जाएगा। यह आयोग राजनीतिक भूगोल का अध्ययन कर रिपोर्ट देगा। आयोग राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में मौजूदा आबादी और उसका लोकसभा एवं विधानसभा क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व का आकलन करेगा। साथ ही राज्य में अनुसूचित व अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित सीटों को सुरक्षित करने का भी अहम् निर्णय लेगा। परिसीमन के नए परिणामों से जो भौगोलिक, सांप्रदायिक और जातिगत असमानताएं हैं, वे दूर होंगी। नतीजतन जम्मू-कश्मीर व लद्दाख क्षेत्र नए उज्जवल चेहरों के रूप में पेश आएंगे।

जम्मू-कश्मीर का करीब 60 प्रतिशत क्षेत्र लद्दाख में है। इसी क्षेत्र में लेह आता है, जो अब लद्दाख की राजधानी हैं। यह क्षेत्र पाकिस्तान और चीन की सीमाएं साझा करता हैं। लगातार 70 साल लद्दाख, कश्मीर के शासकों की बद्नीयति का शिकार होता रहा। अब तक यहां विधानसभा की मात्र चार सीटें थीं, इसलिए राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास को कोई तरजीह नहीं देती थी। लिहाजा आजादी के बाद से ही इस क्षेत्र के लोगों में केंद्र शासित प्रदेश बनाने की चिंगारी सुलग रही थी। अब इस मांग की पूर्ति हो गई है। इस मांग के लिए 1989 में लद्दाख बुद्धिस्ट एसोशिएशन का गठन हुआ और तभी से यह संस्था कश्मीर से अलग होने का आंदोलन छेड़े हुए थी। 2002 में लद्दाख यूनियन टेरेटरी फ्रंट के अस्तित्व में आने के बाद इस मांग ने राजनीतिक रूप ले लिया था। 2005 में इस फ्रंट ने लेह हिल डवलपमेंट काउंसिल की 26 में से 24 सीटें जीत ली थीं। इस सफलता के बाद इसने पीछे मुडकर नहीं देखा। इसी मुद्दे के आधार पर 2004 में थुप्स्तन छिवांग सांसद बने। 2014 में छिवांग भाजपा उम्मीदवार के रूप में लद्दाख से फिर सांसद बने। 2019 में भाजपा ने लद्दाख से जमयांग सेरिंग नामग्याल को उम्मीदवार बनाया और वे जीत भी गए। लेह-लद्दाख क्षेत्र अपनी विषम हिमालयी भौगोलिक परिस्थितियों के कारण साल में छह माह लगभग बंद रहता है। सड़क मार्गों व पुलों का विकास नहीं होने के कारण यहां के लोग अपने ही क्षेत्र में सिमटकर रह जाते हैं।

जम्मू-कश्मीर में अंतिम बार 1995 में परिसीमन हुआ था। राज्य का विलोपित संविधान कहता था कि हर 10 साल में परिसीमन जारी रखते हुए जनसंख्सा के घनत्व के आधार पर विधान व लोकसभा क्षेत्रों

का निर्धारण होना चाहिए। परिसीमन का यही समावेशी नजारिया है। जिससे बीते 10 साल में यदि जनसंख्यात्मक घनत्व की दृष्टि से कोई विसंगति उभर आई है, तो वह दूर हो और समरसता पेश आए। इसी आधार पर राज्य में 2005 में परिसीमन होना था, लेकिन 2002 में तत्कालीन मुख्यमंत्री फारूख अब्दुल्ला ने राज्य संविधान में संशोधन कर 2026 तक इस पर रोक लगा दी थी। इस हेतु बहाना बनाया कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के प्रासंगिक आंकड़े आने तक परिसीमन नहीं होगा।

फिलहाल जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की कुल 111 सीटें हैं। इनमें से 24 सीटें पाक अधिकृत कश्मीर (पीओके) क्षेत्र में आती हैं। इस उम्मीद के चलते ये सीटें खाली रहती हैं कि एक न एक दिन पीओके भारत के कब्जे में आ जाएगा। फिलहाल बाकी 87 सीटों पर चुनाव होता है। इस समय कश्मीर यानी घाटी में 46, जम्मू में 37 और लद्दाख में 4 विधानसभा सीटें हैं। 2011 की जनगणना के आधार पर राज्य में जम्मू संभाग की जनसंख्या 53 लाख 78 हजार 538 है। यह प्रांत की 42.89 प्रतिशत आबादी है। राज्य का 25.93 फीसदी क्षेत्र जम्मू संभाग में आता है। इस क्षेत्र में विधानसभा की 37 सीटें आती हैं। दूसरी तरफ कश्मीर घाटी की आबादी 68 लाख 88 हजार 475 है। प्रदेश की आबादी का यह 54.93 प्रतिशत भाग है। कश्मीर संभाग का क्षेत्रफल राज्य के क्षेत्रफल का 15.73 प्रतिशत है। यहां से कुल 46 विधायक चुने जाते हैं। इसके अलावा राज्य के 58.33 प्रतिशत वाले भू-भाग लद्दाख में संभाग में महज 4 विधानसभा सीटें थीं, जो अब लद्दाख के केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद विलोपित हो जाएंगी। साफ है, जनसंख्यात्मक घनत्व और संभागबार भौगोलिक अनुपात में बड़ी असमानता है, जनहित में इसे दूर किया जाना, एक जिम्मेबार सरकार की जवाबदेही बनती है। परिसीमन के बाद अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए भी सीटों के आरक्षण की नई व्सवस्था लागू हो जाएगी। फिलहाल कश्मीर में एक भी सीट पर जातिगत आरक्षण की सुविधा नहीं है, जबकि इस क्षेत्र में 11 प्रतिशत गुर्जर बकरवाल और गद्दी जनजाति समुदायों की बड़ी आबादी निवास करती है। जम्मू क्षेत्र में जो सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, लेकिन इनमें आजादी से लेकर अब तक क्षेत्र का बदलाव नहीं किया गया है। बहरहाल अब इन केंद्र शासित प्रदेशों में कई ऐसे बदलाव देखने में आएंगे, जो यहां के निवासियों के लिए समावेशी होने के साथ लाभदायी भी साबित होंगे और वे स्वयं इस क्षेत्र को देश की अखंडता व संप्रभुता के लिए जरूरी मानने लग जाएंगे। नरेंद्र मोदी के बीस साल के प्रशासनिक कार्यकाल की यह सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

(लेखक वरिष्ठ साहित्यकार और पत्रकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

किसानों की बदहाली तभी दूर होगी, जब वे बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ेंगे

रमेश कुमार दुबे

आजादी के बाद खेती-किसानी को देश का आत्मा मानते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि 'सब कुछ इंतजार कर सकता है, लेकिन खेती नहीं।' दुर्भाग्यवश लोकलुभावन नीतियों और वोट बैंक की राजनीति के कारण खेती का इंतजार खत्म नहीं हुआ और वह बदहाली का शिकार बनती गई। आज स्थिति यहां तक आ गई है कि ग्रामीण मजदूरों की आमदनी किसानों से ज्यादा हो गई है। 2012-13 में एक औसत भारतीय किसान परिवार की खेती से होने वाली मासिक आमदनी 3,081 रुपये थी। छह साल बाद अर्थात 2018-19 में यह बढ़कर महज 3,798 रुपये पर पहुंची। दूसरी ओर इन छह वर्षों में मजदूरी से होने वाली कमाई 2,071 रुपये से बढ़कर 4,063 रुपये हो गई। पुराने कृषि कानूनों की ही देन है कि अब किसानों से ज्यादा मजदूरों की संख्या बढ़ रही है।

उदाहरण के लिए 2013 से 2019 के बीच खेती करने वाले परिवारों की संख्या जहां नौ करोड़ से बढ़कर 9.3 करोड़ हुई, वहीं कृषि कार्य में शामिल नहीं होने वाले परिवारों की संख्या 6.6 करोड़ से बढ़कर आठ करोड़ पर पहुंच गई। 2011 की जनगणना में भी बताया गया है कि हर रोज 2,000 किसान खेती छोड़ रहे हैं। इसका एक कारण यह भी है कि पारिवारिक बंटवारे से खेतों का आकार इतना छोटा हो गया है कि उनमें खेती लाभकर नहीं रह गई है। खेती के घाटे का सौदा बनने का ही नतीजा है कि किसान का बेटा खेती करने का इच्छुक नहीं है। इतना ही नहीं कृषि विश्वविद्यालयों से स्नातक करने वाले अधिकांश छात्र अन्य व्यवसायों में जा रहे हैं।

एक ओर किसानों की आमदनी में ठहराव आया है तो दूसरी ओर उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए 2012-13 में एक औसत किसान परिवार पर 47,000 रुपये का कर्ज था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 74,121 रुपये हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ओर किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर होती जा रही है तो दूसरी ओर कृषि उपजों के कारोबार में लगी कंपनियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसका कारण है कि जब किसान की उपज बाजार में आती है तब उसके दाम गिर जाते हैं

एक ओर किसानों की आमदनी में ठहराव आया है तो दूसरी ओर उनके ऊपर कर्ज का बोझ भी बढ़ता जा रहा है। उदाहरण के लिए 2012-13 में एक औसत किसान परिवार पर 47,000 रुपये का कर्ज था, जो कि 2018-19 में बढ़कर 74,121 रुपये हो गया। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि एक ओर किसानों की हालत मजदूरों से भी बदतर होती जा रही है तो दूसरी ओर कृषि उपजों के कारोबार में लगी कंपनियों का मुनाफा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है।

और बाद में कई गुना बढ़ जाते हैं। स्पष्ट है भारतीय किसानों की बदहाली की एक बड़ी वजह यह है कि उनकी उपज की वाजिब कीमत नहीं मिलती। इसका कारण है हर स्तर पर बिचौलियों का प्रभुत्व। इनको हटाकर उत्पादकों को सीधे उपभोक्ताओं से जोड़ने की मुहिम में मोदी सरकार जुटी है। इस दिशा में कारगर कदम है इलेक्ट्रानिक मंडी (ई-नाम) और किसान रेल का संचालन।

इस साल गुजरात में आलू की बंपर पैदावार हुई। स्थानीय स्तर पर किसानों को आलू बेचने में समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में गुजरात सरकार ने रेलवे की मदद ली और 50 प्रतिशत छूट पर 248 टन आलू हिम्मतनगर से बिहार के मोतिहारी भेजा गया, जहां आलू की अच्छी कीमत मिली। इसी तरह महाराष्ट्र से प्याज बंगाल और पूवरेत्तर राज्यों को भेजी जा रही है। किसान रेल की विशेषता है कि इसमें किसानों के उत्पाद खराब नहीं होते और कम लागत में जल्दी पहुंच जाते हैं। किसान रेल का बड़ा लाभ यह हुआ कि किसान गेहूं-धान के बजाय फलों एवं सब्जियों की खेती को प्राथमिकता देने लगे हैं।

उल्लेखनीय है कि देश के 8.5 फीसद फसली क्षेत्र पर बागवानी फसलों की खेती की जाती है, लेकिन इनसे कृषिगत सकल घरेलू उत्पाद का 30 फीसद प्राप्त होता है। फलों एवं सब्जियों की खेती अन्य फसलों के मुकाबले चार से दस गुना ज्यादा रिटर्न देती है। शहरीकरण, मध्यवर्ग का विस्तार, बढ़ती आमदनी, खान-पान की आदतों में बदलाव के चलते दुनिया में अनाज के बजाय फलों-सब्जियों की मांग में तेजी से इजाफा हो रहा है। प्रति व्यक्ति आय में एक फीसद की बढ़ोतरी से सब्जी की खपत 1.02 फीसद और फलों की 1.9 फीसद बढ़ जाती है। स्पष्ट है आने वाले वर्षों में फल एवं सब्जी की खपत में तेजी से इजाफा होना तय है, पर समस्या यह है कि चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा फल एवं सब्जी उत्पादक होने के बावजूद भारत इस बाजार में भरपूर हिस्सेदारी नहीं बना पाया है। भारत विश्व का 12.6 फीसद फल एवं 14 फीसद सब्जी उत्पादित करता है, लेकिन फलों एवं सब्जियों के कुल वैश्विक बाजार में उसकी हिस्सेदारी महज 0.5

एवं 1.7 फीसद ही है।

इसी को देखते हुए मोदी सरकार फलों-सब्जियों की खेती को बढ़ावा दे रही है। इसके लिए सरकार कृषि उत्पादक संगठन (एफपीओ) बना रही है। 2020 में शुरू हुई इस योजना के तहत अगले तीन साल में देश भर में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य है। हर एक एफपीओ में 50 प्रतिशत छोटे, सीमांत और भूमिहीन किसान शामिल होंगे। इसके अलावा प्रत्येक एफपीओ के उसके काम के अनुरूप 15 लाख रुपये का अनुदान भी दिया जाएगा। दूसरे शब्दों में किसानों को उद्यमी बनाने का प्रयास है एफपीओ। गांवों में कृषि से जुड़े आधारभूत ढांचा निर्माण के लिए मोदी सरकार ने एक लाख करोड़ रुपये के कोष का गठन किया है। इस फंड से कोल्ड स्टोरेज, वेयरहाउस, ग्रेडिंग और पैकेजिंग इकाइयां लगाने के लिए लोन दिया जा रहा है। इससे गांवों में निजी निवेश आएगा और नौकरियों का सृजन होगा।

समग्रत: मोदी सरकार नए कृषि कानूनों के जरिये किसानों की बदहाली दूर करने और उन्हें मजदूर बनने से रोकने का कारगर उपाय कर रही है। यह काम तभी होगा जब किसान बाजार अर्थव्यवस्था से जुड़ें और अपनी उपज घरेलू एवं वैश्विक कृषि बाजारों में बेचें। दुर्भाग्यवश एक देश-एक मंडी की मांग करने वाले किसान संगठन और 2019 के अपने चुनावी घोषणा पत्र में कृषि उपज के व्यापार पर लगे सभी प्रतिबंधों को समाप्त करने का वादा करने वाली कांग्रेस पार्टी नए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं।

इस साल गुजरात में आलू की बंपर पैदावार हुई। स्थानीय स्तर पर किसानों को आलू बेचने में समस्या खड़ी हो गई। ऐसे में गुजरात सरकार ने रेलवे की मदद ली और 50 प्रतिशत छूट पर 248 टन आलू हिम्मतनगर से बिहार के मोतिहारी भेजा गया, जहां आलू की अच्छी कीमत मिली। इसी तरह महाराष्ट्र से प्याज बंगाल और पूवरेत्तर राज्यों को भेजी जा रही है। किसान रेल की विशेषता है कि इसमें किसानों के उत्पाद खराब नहीं होते और कम लागत में जल्दी पहुंच जाते हैं। किसान रेल का बड़ा लाभ यह हुआ कि किसान गेहूं-धान के बजाय फलों एवं सब्जियों की खेती को प्राथमिकता देने लगे हैं।

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। वरिष्ठ टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं।)

'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' को साकार करती मोदी सरकार

अजय धवले

'स्वच्छ ईंधन, बेहतर जीवन' के नारे के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दृढ़ संकल्प के अनुसार केंद्र सरकार ने 1 मई 2016 को 'प्रधानमंत्री उज्जवला योजना' की शुरुआत की थी। इस योजना के तहत 5 करोड़ परिवारों, विशेषकर गरीबी रेखा से नीचे जीवन बिताने वाली महिलाओं को रियायती एलपीजी कनेक्शन मुहैया कराए गए।

अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।

उज्ज्वला योजना सिर्फ रसोई पकाने के लिए ईंधन मात्र नहीं है, बल्कि जिंदगियों को रोशनी से भर उम्मीदों को उड़ान देने वाली योजना बन चुकी है. अब केंद्र सरकार ने उज्ज्वला योजना के पहले चरण में छूटे लाभार्थियों तक उसका हक पहुंचाने के लिए उज्ज्वला 2.0 की शुरुआत की है. एलपीजी कवरेज को 99.6 फीसदी तक पहुंचा चुकी केंद्र सरकार ने इस बार के आम बजट में 1 करोड़ नए कनेक्शन देने का लक्ष्य रखा है, ताकि शहरों में छुटे हुए वे वर्ग, जिनका कोई स्थायी पता नहीं होता या घूमंतू होते हैं, ऐसे 0.4 फीसदी लोगों की पहचान कर उन्हें रसोई गैस कनेक्शन देना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों और महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है। उज्ज्वला योजना के नए संस्करण में प्रवासी मज़दूरों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है. इसके तहत राशन कार्ड या आधार कार्ड के बजाय सिर्फ़ सेल्फ़ डेक्लरेशन से भी कनेक्शन दिया जाएगा। गैस सिलेंडर और गैस स्टोव के साथ पहला रीफ़िल मुफ्त दिया जाएगा।

अप्रैल 2018 में इस योजना का दायरा बढ़ाया गया और इसमें अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, प्रधानमंत्री आवास योजना, अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों और अति पिछड़ा वर्ग समेत सात श्रेणियों की महिलाओं को भी शामिल किया गया। साथ ही एलपीजी कनेक्शन के लक्ष्य को आठ करोड़ तक बढ़ाया गया जिसे निर्धारित तिथि से सात महीने पहले अगस्त 2019 में हासिल कर लिया गया।

उज्ज्वला योजना के तहत पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने उज्जवला दीदी के नाम से एक पहल की शुरूआत हुई है। इसमें 10,000 महिलाओं को लोगों को शिक्षित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं। ये महिलाएं मुख्य रूप से तीन संदेश देगीं- 1 स्वच्छ घरेलू ईंधन सर्वत्र उपलब्ध है, 2-स्वच्छ घरेलू ईंधन किफायती है, 3-एलपीजी सुरक्षित है और बीमाकृत है। उज्जवला दीदी एलपीजी सुरक्षा से सम्बन्धित किसी भी समस्या को दूर करेंगीं और नए कनेक्शन की सुविधाएं देंगीं। इस प्रकार उज्जवला दीदी अपनी पंचायत में महिलाओं के सशक्तिकरण में भूमिका निभाएंगीं।

27 मार्च, 2015 को प्रधानमंत्री जी ने आर्थिक रूप से संपन्न लोगो एलपीजी कनेक्शन धारकों को सरकार से मिलने वाली सब्सिडी छोड़ने का निवेदन किया था जिसके लिए उन्होंने 'गिव इट अप' का सन्देश लोगो को दिया था। उसी के स्वरुप 1.13 करोड़ से अधिक लोगों ने आर्थिक सब्सिडी को छोड़ दिया था।

उज्ज्वला योजना के सफल क्रियान्वयन से पिछले कुछ वर्षो में एलपीजी क्षेत्र में बड़ी कामयाबी सरकार के हाथ लगी है। नकली उपभोक्ता खत्म हुए हैं। सब्सिडी सही हाथों में पहुंच रही है। साथ ही पहल जैसी योजनाओं के माध्यम से घरेलू गैस के वितरण और उपयोग में पारदर्शिता देखने को मिली है। सब्सिडी को खातों में सीधे भेजे जाने से बिचैलियों और भ्रष्टाचार पर रोक लगी है। इस योजना से एलपीजी डिलीवरी सिस्टम को कारगर बनाने में भी मदद मिली है। भारत के गांवों में खाना बनाने के लिए परंपरागत रूप से लकड़ी और गोबर के उपले का इस्तेमाल किया जाता रहा है। इससे निकलने वाले धुएं का खराब असर खाना बनाने वाली महिलाओं के स्वास्थ्य पर पड़ता है। प्रधानमंत्री उज्जवला योजना से ऐसी महिलाओं को काफी राहत मिली है। गांव में ज्यादातर महिलाओं का समय दो वक्त के ईंधन का व्यवस्था करने में ही गुजरता था। केवल इतना ही नहीं गांव से दूर जंगलों से लकड़ी लाना जोखिम भरा काम भी होता है। वहीं इसके चलते महिलाएं, परिवार और बच्चों को भी समय नहीं दे पाती हैं। लेकिन, उज्जवला योजना ने उन्हें न केवल धुएं के खराब

असर से मुक्ति दिलाई है बल्कि इन तमाम जोखिमों से भी दूर किया है। गौरतलब है की विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़ों के मुताबिक, भारत में रसोई में पारंपरिक ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, उपले आदि पर खाना बनाने की वजह से निकलने वाले धुएं से ही हर वर्ष करीब 5 लाख मौतें होती थी. इसमें अधिकांश महिलाएं होती थी, जिनकी खराब सेहत का असर पूरे परिवार पर स्वाभाविक पड़ता था। वायु प्रदूषण में भी इसका असर दिखता था। इसके बावजूद आजादी के बाद इतने वर्षो तक पूर्ववर्ती सरकारों ने रसोई गैस जैसे स्वच्छ ईंधन को संपन्न वर्ग तक ही सीमित रखा गया। जबकि वे अगर संकल्प के साथ काम करते तो रसोई गैस को आम आदमी के दायरे में ला सकते थे। यदि हम इस योजना के विस्तार के बारे में सोचे तो 60 वर्षो में जहां 55 फीसदी परिवारों तक एलपीजी पहुंची, वहां मोदी सरकार 7 वर्षो में 43 फीसदी की बढ़ोतरी के साथ 99.6 फीसदी परिवारों तक यह पहुंच गई

उज्ज्वला योजना एक ऐसा नीतिगत निर्णय साबित हुई है जिसने गरीब, वंचित, मध्यम वर्ग, अनुसूचित जाति, जनजाति और खासकर महिलाओं के जीवन स्तर को बढ़ाया है गरीब परिवारों को निःशुल्क रसोई गैस कनेक्शन प्राप्त होने से उनके जीवन स्तर में व्यापक परिवर्तन आया है। रसोई गैस कनेक्शन की उपलब्धता महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। यह योजना सचमुच में नारी की गरिमा और उनके स्वास्थ्य की रक्षा के साथ नारी के आत्मसम्मान को सरकार द्वारा दिया गया अनुपम उपहार है।

वास्तव में यह सब प्रधानमंत्री जी की दूरदृष्टि तथा भारतीय समाज में सनातन काल से चली आ रही महिला आत्मसम्मान को गरिमाय स्थान देने के परम्परा को आगे बढ़ाने की मुहीम का ही नतीजा है। चाहे वह बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन हो या फिर स्वच्छता अभियान के तहत शौचालय निर्माण हो या महिलाओ के नाम से जनधन खाते खोलना हो इस सरकार की प्राथमिकताओ का केंद्रबिंदु हमेशा महिला केंद्रित रहा है , जिसके परिणाम स्वरुप ही आज महिलाओ के जीवनस्तर में बदलाव आया है।

(लेखक कॉरपोरेट लॉयर हैं। ये उनके निजी विचार हैं।)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 10 अगस्त 2021 को उत्तर प्रदेश के महोबा में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले (बीपीएल) लाभार्थियों के बीच एलपीजी का कनेक्शन वितरित कर उज्ज्वला योजना के द्वितीय चरण की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से योजना के लाभार्थियों से संवाद करते हुए कहा उज्ज्वला योजना ने देश के जितने लोगों और महिलाओं का जीवन रोशन किया है, वो अभूतपूर्व है।

भारतीय शिक्षा को नया आयाम दे रहे हैं पीएम मोदी

प्रो. निरंजन कुमार

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के सम्पूर्ण शासकीय कार्यकाल के 20 वर्ष पूरे हो चुके हैं, 7 वर्ष से कुछ ज्यादा प्रधानमंत्री के रूप में और लगभग 13 साल गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में. एक सहज प्रश्न उठता है कि इतने लंबे समय के सार्वजनिक जीवन में श्री मोदी के व्यक्तित्व और कृतित्व की क्या तस्वीर उभरती है? गहराई से देखें तो पीएम मोदी का व्यक्तित्व चार आधार स्तंभों पर खड़ा है. एक ओर वे भारतीयता की महान विरासत के पुंजीभूत रूप हैं, तो दूसरी ओर महात्मा गाँधी के विजन से अनुप्राणित. तीसरी ओर वे बाबासाहेब आम्बेडकर के दिए संविधान के प्रति पूर्ण प्रतिबद्ध हैं तो उनके व्यक्तित्व का चौथा स्तम्भ है देश और देशवासियों के हित में सतत समर्पण. पीएम मोदी के व्यक्तित्व की ये चार मूलभूत विशेषताएँ उनकी सभी नीतियों और निर्णयों में दिखाई पड़ती है. इस आलेख में मोदी जी के शिक्षा संबंधित नीतियों और निर्णयों की पड़ताल की जाएगी.

प्रधानमंत्री मोदी के शिक्षा सम्बन्धी नीतियों-निर्णयों को चार श्रेणियों में बांटकर देखा जा सकता है– नीतिगत, आधारभूत संरचना, पाठ्यक्रम की दिशा और नवाचार.

सर्वप्रथम नीतिगत विषय और नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 पर चर्चा. यहाँ जानना महत्वपूर्ण है कि देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)-2020 के एक-एक बिंदु पर स्वयं विस्तार से विचार किया हो. शिक्षा के प्रति मोदीजी की प्रतिबद्धता को तो यह दर्शाता है ही, इससे एनईपी-2020 पर उनकी गहरी छाप भी पड़ी. विश्व इतिहास में यह भी पहली बार हुआ है कि शिक्षा नीति बनाने के लिए देश के चारों दिशाओं से 2.5 लाख ग्राम पंचायतों, 6600 ब्लॉक और 676 जिलों के शिक्षाविदों, वैज्ञानिकों, अध्यापकों, जनप्रतिनिधियों, उद्योगपतियों, अभिभावकों और छात्रों के सवा 2 लाख सुझावों पर मंथन कर जन आकांक्षाओं के अनुरूप एनईपी-2020 साकार हुई. इस रूप में सारी दुनिया में एक लोकतांत्रिक रीति से तैयार हुई यह पहली शिक्षा नीति है, और सच्चे मायने में एक राष्ट्रीय नीति भी.

एनईपी का एक अन्य महत्वपूर्ण बिंदु है 'सबका

साथ, सबका विकास' के लिए 'सबको शिक्षा' देने की महत्वकांक्षी योजना. वर्तमान में 'राइट टू एजुकेशन' आठवीं कक्षा और 14 साल तक के बच्चों के लिए है. लेकिन एनईपी में इससे आगे बढ़कर माध्यमिक स्तर तक 'एजुकेशन फ़ॉर ऑल' का लक्ष्य रखा गया है. अब 18 वर्ष तक सभी के लिए स्कूली शिक्षा अनिवार्य और निशुल्क होगी.

बाबासाहेब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप मोदी सरकार की एनईपी सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े-वंचित तबकों (SEDGs) के लिए भी सजग है. एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों और ईडब्लूएस के मेधावी छात्रों के लिए वर्तमान सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त विशेष प्रावधान किए जाएँगे. यह बात भी अहम है कि सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इन कमजोर तबकों के लिए निशुल्क शिक्षा या छात्रवृति के प्रयास किए जाएँगे. एनईपी में मध्यम वर्ग का भी ध्यान रखा गया है. उन्हें निजी संस्थानों में बेतहाशा फीस न देनी पड़े, इसके लिए निजी संस्थानों की मनमानी फीस पर लगाम लगाने के लिए एक कैपिंग (capping) भी होगी.

मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत का स्वप्न रोजगार से भी है. मैकाले मॉडल पर आधारित हमारी शिक्षाप्रणाली किताबी ज्ञान पर जोर देती है, जो पढ़ाई के बाद नौकरी ढूँढने वाले बेरोजगारों की बड़ी खेप तैयार कर रही है. लेकिन एनईपी पाठ्येतर क्रियाकलापों और वोकेशनल शिक्षा पर भी बल देती है. महात्मा गांधी के श्रम-सिद्धांत के अनुरूप छठी क्लास से ही वोकेशनल कोर्स शुरू होंगे, जिसमें 'कोडिंग' ('व्हाइट हैट जूनियर' तरह के) जैसे आधुनिकतम प्रशिक्षण भी होंगे जिसके लिए प्राइवेट कम्पनियाँ हजारों रूपये फीस वसूलती हैं. बल्कि अमेरिकी-यूरोपीय विश्वविद्यालयों की तरह कॉलेज स्तर पर भी वोकेशनल प्रशिक्षण के विभिन्न कोर्सेस उपलब्ध होंगे जो युवकों को स्वावलम्बन की दिशा में ले जाएँगे. मोदी मॉडल में रोजगार मांगने वालों की जगह रोजगार देने वालों अथवा स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा.

एनईपी-2020 में स्ट्रीम की खांचेबंदी नहीं होगी. अब साइंस अथवा कॉमर्स का छात्र आर्ट्स और सोशल साइंस के विषय भी पढ़ सकेगा. यह पैटर्न छात्रों में एक अंतर्विषयक (Interdisciplinary) दृष्टि पैदा करेगा. मल्टी-टास्किंग के ज़माने में एक तरफ राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पर उनके रोजगार में सहायक होगा तो दूसरी ओर भावी अंतर्विषयक (Interdisciplinary) रिसर्च के लिए उन्हें तैयार करेगा.

इसी तरह मल्टी-एंट्री और मल्टी-एग्जिट ग्रेजुएशन प्रोग्राम की योजना छात्रों खासतौर से वंचित वर्ग के लिए क्रांतिकारी है. अभी किसी कारणवश बीच में ही पढ़ाई छोड़ना पड़े तो सारा धन, परिश्रम तथा समय बर्बाद चला जाता है. लेकिन अब एक साल अथवा दो साल में भी पढ़ाई छोड़ने पर उसे

सर्टिफिकेट या डिप्लोमा जरुर मिलेगा. बल्कि एक तय सीमा में वापस आकर वह अपनी बची पढाई पूरा कर सकता है. 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' यानी एक डिजिटल क्रेडिट बैंक अन्य क्रांतिकारी प्रावधान है जिसमें छात्रों द्वारा विभिन्न कोर्सेस पास करने के बाद प्राप्त क्रेडिट (अंक) जमा होते जाएँगे. किन्हीं मज़बूरी में संस्थान-शहर बदलना पड़े तो एक संस्थान या प्रोग्राम में प्राप्त क्रेडिट को दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाएगा. इससे उनकी अब तक की हुई पढ़ाई व्यर्थ नहीं जाएगी. हर्ष का विषय है कि 'एकेडेमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स' स्थापित भी हो चुका है.

मोदी जी के भारत-प्रेम की झलक भारतीय भाषाओं के प्रति उनके प्रेम में भी दिखती है. इसीलिए एनईपी में स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक 'भारतीय भाषाओँ में अध्यापन' पर बल है. अब कम से कम पाँचवी ग्रेड तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी. यूनेस्को रिपोर्ट-2008 भी मातृभाषा में शिक्षण की अनुशंसा करता है. संसार के विकसित देशों अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, जापान, चीन आदि में स्कूली, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्यतया उनके देश की भाषा ही है. 'भारतीय भाषाओं में अध्यापन' हमारे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाएगा जो अन्ततः राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा.

संरचना के स्तर पर देखें तो भारतीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण पाठ-सामग्री उपलब्ध हो, इसके लिए

बाबासाहेब अंबेडकर की भावनाओं के अनुरूप मोदी सरकार की एनईपी सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़े-वंचित तबकों (SEDGs) के लिए भी सजग है. एससी, एसटी, ओबीसी, दिव्यांगों और ईडब्लूएस के मेधावी छात्रों के लिए वर्तमान सरकारी योजनाओं के अतिरिक्त विशेष प्रावधान किए जाएँगे. यह बात भी अहम है कि सार्वजनिक के अलावा निजी क्षेत्रों के उच्च शिक्षा संस्थानों में भी इन कमजोर तबकों के लिए निशुल्क शिक्षा या छात्रवृति के प्रयास किए जाएँगे.

एक इंस्टीट्यूट ऑफ़ ट्रांसलेशन एंड इंटरप्रिटेशन (आईआईटीआई) की स्थापना की ओर कार्य अग्रसर है. उधर देश में 64 साल में जहाँ 16 आईआईटी बने, वहीं मोदी सरकार ने 7 साल में ही 7 और आईआईटी बनवा दिए. इसी तरह 2014 तक भारत में 13 आईआईएम थे. अब यह संख्या बढ़कर 20 हो चुकी है.

पाठ्यक्रम एक अन्य बिंदु है जहाँ मोदी सरकार ने हमारी शिक्षा को पश्चिमी परिप्रेक्ष्य-दृष्टि के कब्जे से निकालकर भारतीयता से जोड़ने का शुभारंभ किया है. उदाहरण-स्वरूप पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने सार्वजनिक मंच से वैदिक गणित पढने की वकालत की. याद रहे कि आईआईएम तक के कोचिंग में

वैदिक गणित का अभ्यास कराया जाता है. इसी तरह इतिहास में सुहेलदेव जैसे उपेक्षित्त सबाल्टर्न नायकों का उल्लेख कर अकादमिक जगत को प्रेरित किया है. आजादी के अमृत महोत्सव पर प्रधानमंत्री की नवीनतम योजना 'युवा' (YUVA) 30 वर्ष से कम उम्र के लेखकों का एक पूल तैयार करेगी जिससे भारतीय संस्कृति और साहित्य को विश्व स्तर पर पेश करने में मदद मिलेगी.

मोदी जी के भारत-प्रेम की झलक भारतीय भाषाओं के प्रति उनके प्रेम में भी दिखती है. इसीलिए एनईपी में स्कूली से लेकर उच्च शिक्षा तक 'भारतीय भाषाओँ में अध्यापन' पर बल है. अब कम से कम पाँचवी ग्रेड तक की पढ़ाई मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में होगी. यूनेस्को रिपोर्ट-2008 भी मातृभाषा में शिक्षण की अनुशंसा करता है. संसार के विकसित देशों अमेरिका, जर्मनी, फ़्रांस, इंग्लैंड, जापान, चीन आदि में स्कूली, यहाँ तक कि उच्च शिक्षा का माध्यम भी सामान्यतया उनके देश की भाषा ही है. 'भारतीय भाषाओं में अध्यापन' हमारे विद्यार्थियों की अधिगम क्षमता को बढ़ाएगा जो अन्ततः राष्ट्र निर्माण में सहायक होगा.

नवाचार और शोध-अनुसंधान एक अन्य क्षेत्र है जो किसी राष्ट्र की प्रगति में बड़ी भूमिका निभाते है. देश में एक विश्वस्तरीय शोध-अनुसंधान क्षमता विकसित हो, इसके लिए नेशनल रिसर्च फ़ाउंडेशन (एनआरएफ़) की स्थापना हो रही है. 2021 फ़रवरी में मोदी सरकार ने इसके लिए 50,000 करोड़ रूपये मंजूर किया है. यही नहीं, स्कूली छात्रों में भी इनोवेशन/ नवाचार को प्रोत्साहन देने के लिए मोदी सरकार ने 2016 से स्कूलों में अटल टिंकरिंग लैब की शुरुआत कर दिया है. इसके अतिरिक्त नवाचार और शोध-अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए एकल विषयक संस्थानों जैसे लॉ यूनिवर्सिटी या एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी आदि को धीरे-धीरे बहुविषयक संस्थानों (Multidisciplinary Education and Research Universities) में बदल दिया जाएगा.

समग्र रूप से कहें तो भारतीयता से लेकर वैश्विकता, रोजगार से लेकर नवाचार और जन-कल्याण से लेकर आर्थिक प्रगति– सभी दृष्टियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीतियाँ और निर्णय 21वीं सदी के भारत की आवश्यकताओं-चुनौतियों को पूरा करने और हमें आत्मनिर्भर बनाने में सक्षम होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं.

(लेखक दिल्ली विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग, कला संकाय में प्राध्यापक हैं. प्रस्तुत विचार उनके निजी हैं.)

Published by

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001
Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,
Phone:011-69047014

@spmrfoundation

Copyright © Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation
All rights reserved.